साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली
वर्ष-29 अंक- 01 02 -08 जनवरी 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए
तैयार कर दिया विपक्ष के लिए ब्लू प्रिंट पृष्ठ - 4-6-7
चुनाव आते ही क्यों आने लगी मथुरा की याद पृष्ठ-5

लोकसभा का शीतकालीन सत्र छोड़ गया अपने पीछे कई अहम प्रश्न

क्या हमारा राजनैतिक तंत्र उसका हल तलाश करेगा?

हमारे प्रधानमंत्री एक ओर तो संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं और दूसरी ओर उसकी महानता को समाप्त करते हुए बिना किसी राजनैतिक चर्चा के अपने मनमर्जी नियम पास करा रहे हैं।

जिस समय आप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं उस समय लोकसभा का यह शीतकालीन सत्र अपना आखिरी दिन भी पूरा कर चुका है। यह अधिवेशन भी अधिकतर गतिरोध का ही शिकार रहा, राज्यसभा तो पूरे माह लगभग ठप्प ही रही, इस लिए की राज्यसभा के इजलास के पहले ही दिन चेयरमेन वैंकैय्या नायडू ने विपक्षी दल के उन 12 सदस्यों को अधिवेश की पूरी मुद्दत के लिए सदन से निलंबित कर दिया था उन पर आरोप था कि उन्होंने लोकसभा के सत्र के दौरान सदन में बुरा व्यवहार करते हुए सदन की कार्रवाई में गतिरोध डालने का प्रयास किया था। चेयरमैन के इस आदेश के विरुद्ध राज्यसभा में पूरा विपक्षी दल उठ खड़ा रहा, निलंबित सदस्यों ने गांधी जी की प्रतिमा के पास धरना दे दिया और विपक्षी पार्टियों ने उनकी वापसी की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी जबकि चेयरमैन का कहना था कि जब तक यह सदस्य माफी नहीं मांगेंगे तो उनकी वापसी नहीं होगी, जिसकी वजह से राज्यसभा में कोई अहम काम नहीं हो सका और उसका अधिकतर समय गतिरोध की भेंट चढ़ता रहा, अब सवाल यह है कि आख़िर इसका उत्तरदायित्व किस पर है।

बीते वर्ष 2021 के 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाया। 26 नवंबर 1949 को देश ने अपना संविधान पूरा करके उस पर हस्ताक्षर किए थे। हमारे संविधान निर्माताओं के ये हस्ताक्षर देश के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हस्ताक्षर कुल मिलाकर इस बात की सहमति और स्वीकृत है कि देश का संविधान सर्वोपरि है। हमारे प्रधानमंत्री कई बार इसे हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ कह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब सांसद बनकर पहली बार संसद भवन पहुंचे थे तो उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर सिर झुकाकर जनतंत्र के सर्वोच्च मंदिर को प्रणाम किया था।

जनतंत्र का यह मंदिर और धर्मग्रंथ दोनों, हमारे देश की गरिमा के प्रतीक हैं। इनका सम्मान उन मूल्यों और आदेशों का सम्मान है जो जनतंत्रिक व्यवस्था की महत्ता को रेखांकित करते हैं। उस दिन जब संसद में संविधान दिवस मनाया गया तो सांसदों को प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति ने भी संबोधित किया था। एक चीज़ जो खलने वाली थी, वह कार्यक्रम का विपक्ष द्वारा बहिष्कार था। इस निर्णय के कारण हो सकते हैं, पर जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान की गरिमा का तकाज़ा था कि संसद के सभी पक्ष वहां उपस्थित होते। यह कार्यक्रम सरकार का नहीं था, पूरी संसद का था।

संविधान में अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करने के इस अवसर को किसी भी पक्ष द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बनाना उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार और विपक्ष दोनों का कर्तव्य बनता था कि वे इस अवसर की गरिमा और पवित्रता की रक्षा के प्रति सजग दिखाई देते। पर ऐसा हुआ नहीं। दोनों पक्षों की बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए थी इस कार्यक्रम में। सभी पक्षों को अवसर मिलना चाहिए था संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को स्वर देने का यह सहभागिता ही जनतांत्रिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाती है। गरिमा प्रदान करती है।

अच्छी बात है कि इस सहभागिता को संसद का सत्र प्रारंभ होने से पहले प्रधानमंत्री ने फिर से रेखांकित किया। इसे सुनिश्चित करने का काम भी मुख्यतः सत्ता पक्ष को ही करना होता है। पर, दुर्भाग्य से संसद के पिछले कई सत्रों में सहभागिता की भावना का अभाव दिखाई दिया है। दोनों पक्ष इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा सकते हैं, ठहराते भी हैं। लेकिन इस बात को भुलाया नहीं जाना चाहिए कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले इसका दायित्व मुख्यतः सत्तारुढ़ पक्ष पर ही होता है। जनतंत्र में यह अवसर संसद के कामकाज में सहभागिता से परिभाषित होता है। सहभागिता का अर्थ है विचार विमर्श में हिस्सेदारी। मुद्दों पर बहस ही वह माध्यम है जिससे सदन में सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित होती है लेकिन जिस तरह से संसद में विवादास्पद कृषि क़ानूनों की वापसी का विधेयक पारित हुआ, वह इस सहभागिता को अंगूठा दिखाने वाला काम ही कहा जा सकता है। लोकसभा में सिर्फ तीन मिनट और राज्यसभा में नौ मिनट में इन क़ानूनों को वापस ले लिया गया। क़ानूनों की वापसी करने का निर्णय लेने में सरकार को पूरा एक वर्ष लग गया, मिनटों में क़ानून को निरस्त कर दिया गया। कोई बहस नहीं कोई विचार विमर्श नहीं। संसद को इस बारे में सरकार से प्रश्न-उत्तर का अवसर मिलना चाहिए ही था।

इस बात को भुलाया नहीं जाना चाहिए कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले इसका दायित्व मुख्यतः सत्तारुढ़ पक्ष पर ही होता है। जनतंत्र में यह अवसर संसद के कामकाज में सहभागिता से परिभाषित होता है। सहभागिता का अर्थ है विचार विमर्श में हिस्सेदारी। मुद्दों पर बहस ही वह माध्यम है जिससे सदन में सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित होती है लेकिन जिस तरह से संसद में विवादास्पद कृषि क़ानूनों की वापसी का विधेयक पारित हुआ, वह इस सहभागिता को अंगूठा दिखाने वाला काम ही कहा जा सकता है। लोकसभा में सिर्फ तीन मिनट और राज्यसभा में नौ मिनट में इन क़ानूनों को वापस ले लिया गया। क़ानूनों की वापसी करने का निर्णय लेने में सरकार को पूरा एक वर्ष लग गया, मिनटों में क़ानून को निरस्त कर दिया गया। कोई बहस नहीं कोई विचार विमर्श नहीं। संसद को इस बारे में सरकार से प्रश्न-उत्तर का अवसर मिलना चाहिए ही था।

यह क़ानून वापस लेने के कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि सरकार खुले दिमाग़ से हर मुद्दे पर सभी सवालों के हवाल देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री सदन में सार्थक बहस की अपेक्षा कई बार कर चुके हैं कई बार कह चुके हैं कि गरिमापूर्ण, गंभीर बहस होनी चाहिए। संसद की गरिमा और महत्व का तक़ाज़ा है कि सांसदों को गंभीर बहस का अवसर मिले। मुद्दों पर विचार विमर्श हो।

बहरहाल, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत को अच्छा तो नहीं कहा जा सका तो अंत को भी बेकार ही कहा जाएगा। यह कोई शुभ संकेत नहीं है कि पक्ष, विपक्ष और सरकार, इस संदर्भ में अपने अपने दामन में झांकेंगे। विपक्ष सिर्फ आलोचना करने या रोड़े अटकाने के लिए ही नहीं होता, रास्ता सुझाने के लिए भी होता है। यह बात सरकारी पक्ष को भी समझनी चाहिए। सरकार को यह भी समझना चाहिए कि मतदाता ने सिर्फ सरकार को ही नहीं चुना है विपक्ष को भी चुना है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे को बोलने का अवसर दें। कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री के निर्णय को उनके समर्थक राष्ट्र हित में लिया गया महान निर्णय बता रहे थे, लेकिन यह बात सदन में होती तो बेहतर साबित हो पाती। तब यह पूछा जा सकता था कि कृषि क़ानूनों के संदर्भ में वह क्या था जो राष्ट्र हित में था? इस तरह के अवसर बहस से ही मिल सकते

बाक़ी पेज 11 पर

काबुल तक पहुंचने की राह का रोड़ा

अफ़ग़ानिस्तान के नए तालिबान शासकों से रिश्ता कायम करने के लिए भारत के लिए दरवाज़े ज़रूर खुल गए हैं, लेकिन कुछ हद ही। पहले बिना किसी मित्र की मौजूदगी और अब एक ऐसे समूह के साथ व्यवहार कर, जिसे दोनों पक्ष अविश्वास और शत्रुता से देखते हैं, ऐसा लगता है कि भारत ने कई सप्ताहों की सतर्कता के बाद अफ़ग़ानिस्तान में एक अस्थायी शुरुआत की है। भारत ने अफ़ग़ानों के लिए, 1.5 टन चिकित्सा संबंधी और पचास टन खाद्यान्न की आपूर्ति की शुरूआत की है, जो कि चार माह पहले तालिबान के कमान संभालने के बाद से और अधिक कुपोषण तथा भुखमरी का सामना कर रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था तकरीबन तबाह हो चुकी है। इन सामान की आपूर्ति भारत के लिए आसान नहीं थी। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि भारत से कोई सामान अफ़ग़ानिस्तान तक पहुंचे। उसने यह जताने की कोशिश की कि इस बेहद ज़रूरी मानवीय मदद को मंजूरी देना ऐसा है, मानो पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत को अफ़ग़ानिस्तान में व्यावहारिक गतिविधियां शुरू करने की मंज़ूरी देना। वह व्यावसायिक गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय मदद में फर्क करने को तैयार नहीं था।

यहां से दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन को भेजी जा रही है, जिन्हें वह काबुल स्थित इन्दिरा गाँधी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल को भेजेगा। अफ़ग़ानों के लिए पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। भारत जो खाद्यान्न भेज रहा है, उसके पीछे कोई व्यावसायिक मंशा नहीं है। वहां इसकी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इसकी आपूर्ति कम हो गई है। चारों ओर ज़मीन से घिरे अफ़ग़ानिस्तान के सत्ता में आने से पहले से आपूर्ति जारी रखने में नाकाम रहा है। भारत को मंज़ूरी न देना उसका पुराना हथकंडा है, जिसके ज़रिये वह स्थानीय भावनाओं और व्यापारियों को खुश करने की कोशिश करता है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के ज़रिये बिस्कुट की आपूर्ति करने का आग्रह किया था। ये पोषक बिस्कुट अफ़ग़ान बच्चों के लिए भेजे जाने थे। पाकिस्तान द्वारा काबुल ले जाने की अनुमति न देने पर इनका भंडार बाघा बार्डर पर पड़ा और अंततः सड़कर नष्ट हो गया। अतीत के ऐसे कई अनुभवों के कारण अफ़ग़ानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री तथा तालिबान के वरिष्ठ नेता आमित ख़ान मुत्ताकी ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को राज़ी करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। ख़ान के पास भारतीय आपूर्ति को मंज़ूरी देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन यह मंज़ूरी भी एकमुश्त ही दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी शर्तें भी रखीं। भारतीय आपूर्ति सिर्फ अफ़ग़ान ट्रकों के ज़रिये ही हो सकती है। आपूर्ति दिसंबा के आख़िर तक पूरी हो जानी चाहिए। केवल पचास अफ़ग़ान ट्रक ही अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की मुख्य सीमा चौकी तोरखम तक जा सकते हैं। ऐसे में भारी भरकम आपूर्ति महज़ दो से तीन सप्ताह में पूरी करना चुनौती है। क्या इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी बाज़ारों के अवाले कर दिया जाएगा? यह सब तब हो रहा है, जब पाकिस्तान सारी दुनिया से अफ़ग़ान लोगों को मानवीय सहायता देने की अपील कर रहा है और सारा श्रेय खुद लेना चाहता है।

खाद्य और दवाओं की आपूर्ति ने भारत-अफ़ग़ान सहयोग को पुनर्जीवित करने के दरवाज़े खोले हैं। वहां भारत के एकमात्र ज्ञात मित्र हैं तालिबान के कार्यवाहक विदेश उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई। तालिबान से जुड़ने से पहले 1980 के दशक में एक अफ़ग़ान सैन्य अधिकारी के रूप में उन्होंने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लिया था। यहां तक कि वह भी अतीत में भारत पर हमेशा अफ़ग़ान लोगों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा चुके हैं। बदली हुई परिस्थितियों में स्टेनकजई, जिन्हें कभी उनके साथ भारतीय अधिकारी शेरू कहते थे, भारतीय राजनयिकों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने भारत की ओर से दवाओं और खाद्य सामग्री के रूप में की जा

बाक़ी पेज 11 पर

दिल्ली विधानसभा में दीवार के पीछे मिला ऐतिहासिक फांसीघर

विधानसभा में फांसीघर में फांसी देने के लिए बना करीब एक सदी पुराना ढांचा मिला है, जिसमें दो लोगों को एकसाथ फांसी लटकाए जाने की गहरारी लगी हुई है। दिल्ली विधानसभा में इसे संरक्षित किया जाएगा। इस ढांचे की आयु की सही जानकारी के लिए विधान सभा इसकी कॉर्बन डेटिंग कराएगी। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल इसके लिए जल्द ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को पत्र लिखेंगे। विधानसभा में फांसीघर होने की चर्चाओं के आधार पर बंद दो मंज़िला इमारत की दीवार तोड़ी गई थी। 1926 के बाद अंग्रेज़ों ने यहां अदालत बनाई थी। पूर्व में यहां सुरंग मिल चुकी है।

फांसीघर के मिले इस ढांचे में दो स्टैंड हैं और उनके ऊपर फांसी देने के लिए उपयोग में आने वाली रस्सी के लिए दो अलग अलग गरारी लगी है। इसके मिलने के बाद इमारत की पहली मंज़िल पर एक कमरे में बनी पूरी दीवार हटाई जाएगी। इसकी जगह कांच की दीवार बनाई जाएगी। फांसीघर को मंदिर का रूप दिया जाएगा। यहां तक पहुंचने के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी और इसके दूसरी ओर सीढ़ियां बनाई जाएंगी। इमारत की पहली मंदिर पर स्थित फांसीघर और करीब सौ वर्ष पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों को संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा इमारत के भूतल पर एक दीवार तोड़ी जाएगी जिससे यहां आने वाली सुरंग का छोर ढूंढा जा सके। विधानसभा अध्यक्ष गोयल ने कहा कि विधान सभा सदर में जो सुरंग मिली है, उसका एक रास्ता इस फांसीघर की ओर जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस समय सुरंग मिली थी उसी समय यह बात उनके दिमाग़ में आई थी कि यहीं कहीं फांसीघर भी होगा। इसके लिए पुराने कर्मचारियों की मदद से जानकारी जुटाई और सालों से बंद इमारत की पहली मंज़िल पर स्थिति इस कमरे को खुलवाया था, मगर उसमें फांसीघर नहीं मिला था।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि फांसीघर उनके लिए मंदिर से कम नहीं है। यहां उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिससे देश आज़ाद हो सका। उन्होंने कहा कि इस कमरे को स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में तीर्थस्थल में बदला जाएगा। अगले वर्ष तक पर्यटक भी इसे देखने आ सकेंगे। इसके इतिहास को खोज करने की कोशिश की, लेकिन न ही सुरंग और न ही फांसीघर का कोई इतिहास मिला है। विधानसभा इमारत के उपयोग से संबंधित दस्तावेज़ ग़ायब है। इसके लिए केन्द्र सरकार और लोकसभा अध्यक्ष से मदद मांगी है, लेकिन अभी पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। ❑❑

भाजपा शासित एमसीडी अपने कामों में फेल : भारद्वाज

पिछले कई दिनों से वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भाजपा शासित नगर निगमों पर हमलावर रही आप पार्टी (आप) ने अब नगर निगमों पर गाय के बहाने नये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आप के मुख्य प्रवक्ता और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में गायों की भूख से दर्दनाक मौतें हो रही हैं क्योंकि एमसीडी ने चारे के लिए तीन-तीन साल से करोड़ों रुपए का हिस्सा नहीं दिया है। गौशालाओं के चारे के लिए 40 रुपए प्रति गाय जमा किया जाता है, जिसमें 20 रुपए दिल्ली सरकार और 20 रुपए एमसीडी देती है। दिल्ली सरकार से पैसा मिलने के बादवजूद एमसीडी गायों का संरक्षण करने में फेल साबित हुई है। नॉर्थ एमसीडी के चारे का करीब 32 करोड़ रुपया बक़ाया है, साउथ एमसीडी ने फरवरी 2021 से पैसा नहीं दिया है और ईस्ट एमसीडी ने पिछले 3 सालों से पैसा नहीं दिया है। दूध देने वाली गायों को नीलाम करके एमसीडी राज्य से बाहर भेजती है और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें वापस दिल्ली ले आती है। इसके जवाब में दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा हे कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप पार्टी नेता दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव, ठप होती डीटीसी बस सेवा, सरकारी स्कूलों के टीचरों आदि के बदहाली को छुपाने हेतु लोगों को गुमराह करने की राह पर चल पड़े हैं और नागरिकों का ध्यान मैन मुद्दों से भटकाने के लिए रोज़ पगर निगमों पर आरोप लगाते रहते हैं। अब जब नगर निगमों के विरुद्ध मुद्दे नहीं मिलते तो एक सप्ताह में दो तीन बार एक ही मुद्दे पर बोलते है। आप पार्टी ने एक सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली के अर्बन गांवों में लोगों के द्वारा गाय पालने काम मुद्दा उठाया और इसे ग़ैर कानूनी बताया। आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दे से जनता को गुमराह करने की नीति अपना रही है।

जनसंख्या में वृद्धि का प्रोपगंडा वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा

भारत जो एक आज़ाद और लोकतंत्र देश है जहां अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक ताक़तों ने जो सूरतेहाल उत्पन्न कर दी है वह किसी से छुपी नहीं है उन के ख़िलाफ़ वह तमाम दुष्प्रचार और प्रचार किये जा रहे हैं जो उन्हें देश का दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने में मददगार हो सकेंग। कई बार तो ऐसा मालूम होने लगता है कि यह साम्प्रदायिक तत्व जो संख्या में कम होते हैं अपने आप को देश का मालिक समझने लगते हैं, वह यह तय करने लगे है कि क्या खाएं क्या पिएं और क्या नहीं। अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में जिस तरह रेहड़ी पटरी वालों को वहां की कापोरेशन ने गोश्त और उनसे बनी चीज़ों को बेचने के आरोपों में रोज़गार से वंचित किया वह इसकी ताज़ा मिसाल है यह तो अच्छा कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए और उच्च न्यायालय ने कार्पोरेशन के अधिकारियों की निंदा करते हुए उनसे पूछा कि वह लोगों के खानपान का निर्णय करने वाले कौन होते हैं गाय के गोश्त के नाम पर मॉबलिंचिंग की घटनाओं को अभी अधिक समय नहीं हुआ है और उसकी पीड़ा अभी भी ताज़ा है। हरियाणा के गुरुग्राम में जुमा की नमाज़ पढ़ने से रोकने की घटना और खुद मुख्यमंत्री का यह बयान कि खुले में नमाज़ अदा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अभी बिल्कुल हाल की घटना है। यह साम्प्रदायिक तत्व देश की बहुसंख्यक को यह दिखाने की कोशिश में है कि देश में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हो रही है और अगर यह जारी रहा तो बहुसंख्या में आकर सत्ता पर अधिग्रहण कर लेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि साम्प्रदायिक तत्वों का यह प्रचार केवल उनकी काल्पनिक बात है जिसे वे केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वह मुसलमानों की आबादी में वृद्धि के साथ बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों का मुद्दा भी उछाल रहे हैं। मगर उन दोनों मुद्दों पर उन्हें हाल ही में उस समय बड़ा झटका लगा जब खुद देश के विश्वसनीय संस्थाओं के ज़रिए तैयार किए आंकड़ो ने उनके काल्पनिक झूठ की नींव हिला दी, यह रिपोर्ट अरमीका के प्यूरिसर्च सेंटर ने तैयार की है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद के पहले दशक में मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली, मगर वह जल्द ही कम होती चली गयी और यह हो सकता है कि बहुत जल्द दोनों क़ौमों की जनसंख्या फटिर्लिटी का अनुपात बराबरी पर आ जाए। क्योंकि साल 2011 में 14.25 प्रतिशत हो गए। वहीं हिन्दुओं का हिस्सा इसी दौरान लगभग 84 प्रतिशत से घटकर 80 फीसदी पर आ गया। छह दशकों के दौरान आबादी में मुसलमानों का हिस्सा करीब साढ़े चार प्रतिशत बढ़ा। ऐसा अचानक नहीं हुआ। यह बढ़ोत्तरी धीरे धीरे हुई। लेकिन अगर यही ट्रेंड बना रहा तो भी इस सदी के अंत तक आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 20 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगा। बल्कि बढ़ोत्तरी कम ही रहेगी क्योंकि मुसलमानों और हिन्दुओं के बच्चे होने की दर में जो अंतर है, वह तेज़ी से घट रहा है। हो सकता है कि दोनों का रेट जल्द जैसा हो जाए।

1992 से 2015 तक के लिए जो नेशनी फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया, वह फर्टिलिटी से जुड़े आंकड़ों का सबसे भरोसेमंद ज़रिया है। इस दौरान मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट 4.4 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत पर आ गया। फर्टिलिटी रेट का मतलब यह है कि एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। हिन्दुओं के मामले में फर्टिलिटी रेट 3.3 से घटकर 2.1 पर आ गया, लेकिन इसके घटने की रफ्तार मुसलमानों के मुक़ाबले कम रही। इससे साफ है कि मुसलमानों ने फैमिली प्लेनिंग को भले ही देर से अपनाया हो, लेकिन अब इस पर अमल करने में वे हिन्दुओं से आगे हैं।

एक वक़्त था जब ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों में से आधे बचपन में ही मर जाते थे। ऐसे में मां-बाप इसलिए भी ज़्यादा बच्चे होने पर जोर देते थे कि जो बचेंगे, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ मां-बाप को समझ में आने लगता है कि जो कुछ उनके पास है, उसे वे कुछ बच्चों को बेहतर बनाने में लगाएं ताकि उनकी ज़िन्दगी अच्छी रहे। इसी वजह से आमदनी बढ़ने के साथ फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी जाती है। दुनियाभर में ऐसा ही होता है। भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट में दिख रही कमी कोई नहीं बात नहीं है। मुसलमानों की माली हालत चूंकि कमज़ोर है, लिहाज़ा 2.1 के फर्टिलिटी रेट तक पहुंचने में उन्हें ज़्यादा समय लगेगा। फर्टिलिटी रेट 2.1 होने का मतलब यह है कि हर महिला के औसतन दो बच्चे ही होंगे। इस तरह वे आबादी में आगे चलकर अपने मां-बाप की जगह लेंगे और जनसंख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

भारत में मुसलमानों के मुक़ाबले हिन्दुओं की आबादी बढ़ने की रफ्तार कम होने की कुछ ऐतिहासिक वजहें भी है। सबसे अहम कारण यह है कि हिन्दू परंपरा में विधवा विवाह की मनाही थी। वहीं, मुस्लिमों में जल्द दोबारा शादी करने को बढ़ावा दिया जाता था। पहले के दशकों में पुरुषों की मृत्यु दर आज के मुक़ाबले ज़्यादा थी। बाल विवाह भी आम थे और अगर दूल्हा किशोर आयु के पहले ही मर गया तो लड़की बाल विधवा हो जाती। ऐसी सूरत में उसके बच्चे पैदा होने का सवाल ही नहीं था। कामकाज के लिए घर छोड़कर परदेस जाने का भी आबादी से नाता रहा। मुसलमानों के मुक़ाबले हिन्दुओं में ऐसे लोगों की संख्या अधिक हुआ करती थी, जो परदेस जाते थे। पत्नी से दूर रहने का मतलब था कि बच्चे कम ही होंगे।

प्यू सेंटर ने दर्ज किया है कि 1992 में मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच फर्टिलिटी गैप 1.1 बच्चों का था। यानि मुस्लिम महिला हिन्दू महिला के मुक़ाबले औसतन एक बच्चा ज़्यादा पैदा कर रही थी। 2015 आते-आते यह अंतर घटकर 0.5 बच्चों पर आ गया। अगर यही ट्रैंड बना रहा तो बमुश्किल 20 साल में यह अंतर भी ख़त्म हो जाएगा। यानि कुल मिलाकर यह बात है कि चाहे जो कहा जा रहा हो, भारत में हिन्दुओं की विशाल संख्या को कोई ख़तरा नहीं है।

आबादी के तमाम समुदायों की हिस्सेदारी में जो बदलाव आ रहा है, उसका एक और कारण माइग्रेशन है। भारत से बाहर जाने वालों की तादाद विदेश से यहां आने वालों के मुक़ाबले तीन गुनी हैं भारी में जनमे लगभग डेढ़ करोड़ लोग 2015 से विदेश में रह रहे थे। वहीं विदेश में जनमे, लेकिन भारत में रह रहे लोगों की तादाद थी केवल 56 लाख। इनमें से सबसे ज़्यादा 32 लाख लोग आए थे बांग्लादेश से। पाकिस्तान से 11 लाख, नेपाल से पांच लाख 40 हजार और श्रीलंका से एक लाख 60 हज़ार लोग आए। इनमें तमाम हिन्दू है।

मुसलमानों की बात करें तो भारत आने वालों से कहीं ज़्यादा संख्या उन लोगों की है, जो यहां से विदेश गए। भारत की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत है, लेकिन भारत से बाहर जाने वालों में इनका हिस्सा 27 प्रतिशत है। वही, कुल आबादी में हिन्दू है। 79 प्रतिशत लेकिन विदेश जाने वालों में इनका हिस्सा महज़ 45 फीसदी है। यह सारी जानकारी जो आपके सामने रखी, उससे कैसी तस्वीर बन रही है? मुसलमानों की संख्या और बाहर से आने वालों के बारे में भाजपा चाहे जितना हो हल्ला बचाए, उसके आरोपों में कोई दम नहीं है। फिज़ूल का ख़तरा दिखाकर हिन्दुओं को डराने की कोशिश की जाती है ताकि उनके वोट मिल सके।▫▫

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त-104

अहले बिदअ़त को हौज़े कौसर से धुतकार दिया जायेगा

फिर आप ने फ़रमाया कि जब मैं हौज़ पर रहुंगा, तो दूर से मालूम होगा कि यह मेरी उम्मत के लोग हैं, मगर सिक्यूरिटी वाले फ़रिश्ते उन्हें मेरे हौज़ पर आने नहीं देंगे, तो मैं दूर से पुकारूंगा।

''ये मेरे लोग हैं, ''ये मेरे लोग हैं'', रास्ता छोड़ दो।

मगर सिक्यूरिटी वाले फ़रिश्ते हुज़ूर से आकर अर्ज़ करेंगे कि : ''या रसूलल्लाह! आप के दुनिया से परदा फ़रमाने के बाद इन्होंने बहुत गड़बड़ मामला कर रखा था, बड़ी बिदअ़तें ईजाद कर दी थीं''। इस लिए ये लोग अभी आप के दरबार में आने के क़ाबिल नहीं हैं, पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि मैं कहुंगा:

''यहाँ से दफ़ा हो, तुम यहाँ आने के लायक़ नहीं, तुम ने मेरे बाद मेरे दीन को बदल डाला था'' (मुस्लिम शरीफ़ 2/294) पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम इस बात से बड़ी कुढ़न में हैं कि उम्मत सुन्नतों को छोड़ कर बिदअ़तों को इख़्तियार करे, कोई भी बिदअ़त जो आप अ़लैहिस्सलाम और आप के सहाबा से साबित नहीं है, उसके बारे में पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि वह मरदूद है। जो नमूना पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम के तरीक़ा के मुताबिक़ है अल्लाह के यहाँ बस वही मंज़ूर है।

आप में से बहुत से लोग ताजिर होंगे, आप जानते हैं कि ऑर्डर देने वाला नमूने के साथ ऑर्डर देता है कि इतना वज़न, यह फूल बूटे, यह साइज़ चाहिये, आप को बड़ी हमदर्दी आ गई और आप उससे ज़्यादा वज़न का नमूना बना कर ले आये, तो बताओ ऑर्डर देने वाला उसे क़ुबूल करेगा या रिजेक्ट कर देगा?

इसी तरह अल्लाह तआ़ला ने पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम की ज़ात को नमूना बनाया, फ़रमाया:

''अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है।''

नमाज़ ऐसी चाहिये कि जो पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम के नमूने के मुताबिक़ हो, रोज़ा ऐसा चाहिये जो पैग़म्बर के नमूने के मुताबिक़ हो, हज ऐसा चाहिये जो पैग़म्बर के नमूने के मुताबिक़ हो, हर इबादत ऐसी चाहिये जो पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम के तरीक़ा-ए-कार से पूरी तरह मुवाफ़क़त रखती हो, तो अल्लाह के यहाँ क़ुबूल है।

ख़ुलासा यह है कि पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने जब ये सब बातें फ़रमा दीं तो सहाबा से फ़रमाया कि: ''क्या मैंने अल्लाह का पैग़ाम तुम तक पहुंचा दिया?''

सब ने बयक आवाज़ कहा क़सम है अल्लाह की कि आप ने अल्लाह की हर अमानत जूँ कि तूँ पहुंचा दी, तो आप ने शहादत की उंगली उठाई और फ़रमाया:

ऐ अल्लाह गवाह रहियेगा मैंने अपनी ज़िम्मेदारी इन पर पूरी कर दी।

फिर आप ने यह ऐलान फ़रमाया कि उम्मत के लोगो सुन लो! मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें मज़बूती से पकड़े रहे, तो तुम्हें कोई अपनी जगह से हिला नहीं पायेगा। (1) अल्लाह की किताब और (2) सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। (मुस्तदरक हाकिम जि. 1 स. 171, हयातुस्सहाबा 3/402) यानी अल्लाह की किताब और सुन्नते रसूलुल्लाह से लगे रहो, तो दुनिया की कोई ताक़त तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती, पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने ये सब ऐलानात मिना और अरफ़ात में कई मौक़ों पर फ़रमाये।

उसके बाद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का मुअ़ज़्ज़मा तशरीफ़ लाए, और आख़िरी तवाफ़ ''तवाफ़े विदा'' फ़रमाया, और फिर आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, यह मुहर्रमुल हराम से तक़रीबन आठ या दस दिन पहले का वक़्त है। यहाँ आकर भी पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम मुख़्तलिफ़ उमूर, मुहिम्मात और दीन की तकमील में मसरूफ़ रहे। (जारी)

तैयार कर दिया विपक्ष के लिए ब्लू प्रिंट

प्रशांत किशोर

इत्तेफाकन चुनावी रणनीतिकार बने प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ही कमाल का रहा है, वे नरेन्द्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, एम. के. स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह तक सियासी फलक पर तमाम नेताओं को अपने मशवरों से नवाज़ चुके हैं। उन्होंने नौ चुनावों की रणनीति बनाने में मदद की। इनमें से आठ में उनकी रणनीति ने जीत के झंडे गाड़े। सबसे ताज़ा तरीन मई 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव था। इसमें ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीतकर तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनीं, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने खेल में अपनी हर मुमकिन ताक़त झोंक दी थी। तमिलनाडू में स्टालिन ने भी जीत हासिल की, एकमात्र चुनाव जो किशोर हारे, वह 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जिताने का जतन किया था। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ 2010 में उस समय गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक मुलाकात के बाद पोल एडवोकेसी यानि वे चुनावी हिमायत के खतरनाक पेशे में कूद पड़े। भविष्योन्मुखी मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सलाह देने के साथ शुरू हुआ सिलसिला मोदी के भाषण लिखकर गुजरात सरकार को ताक़तवर खुराक देने के अभियान में बदल गया। किशोर बताते हैं कि ''एक के बाद दूसरी चीज़ें होती गईं और मैं उनके राजनैतिक अभियानों से जुड़ता गया।'' उन्होंने 2012 में फिर चुनकर आने के बेहद सफल अभियान में मोदी की मदद की और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के उनके अभियान से औपचारिक तौर पर जुड़ गए। किशोर जोर देकर कहते है। कि अब वे आइ-पीएसी से औपचारिक तौर पर जुड़े नहीं रह गए हैं और इन दिनों एक ऐसा राजनैतिक ताना-बाना बुनने में व्यस्त हैं जो 2024 के आम चुनाव में भाजपा को असरदार चुनौती दे। यहां हम पेश कर रहे हैं प्रशांत किशोर से हुई एक विस्तृत बातचीत।

प्रश्नः- हाल ही में एक टवीट में आपने कहा कि ''कांग्रेस जिस विचार और स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, वह मज़बूत विपक्ष के लिए अत्यंत सक्षम है। मगर कांग्रेस का नेतृत्व एक व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है, विशेषकर जब पार्टी बीते 10 सालों में 90 फीसदी से ज़्यादा चुनाव हार चुकी है। विपक्ष का नेतृत्व लोकतांत्रिक ढंग से घोषित होने दिया जाए।'' साफ है कि आप कांग्रेस नेतृत्व पर हमला कर रहे हैं, पार्टी पर नहीं। वह क्या था जिसने आपको ऐसा करने के लिए उकसाया.?

उत्तरः- इरादा किसी पर हमला करने का नहीं। हाल की पूरी बहस यह हे कि प्रभावी विपक्ष का मतलब कांग्रेस के साथ विपक्ष है या कांग्रेस के बिना विपक्ष है। अपने टवीट में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि कांग्रेस जिस विचार और स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, वह इस देश में प्रभावी विपक्ष के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर कांग्रेस पार्टी, वह विचार या स्थान, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है वही नहीं हे जो कांग्रेस अपनी मौजूदा बनावट में है। मौजूदा नेतृत्व के मातहत कांग्रेस ने बहुत अच्छा नहीं किया है। बीते 10 सालों में, 50 से ज़्यादा राज्य और आम, दोनों चुनावों में, वह करीब 90 फीसदी हारी है। बस कर्नाटक के 2012 के राज्य चुनाव, पंजाब के 2017 के चुनाव और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2018 के चुनाव छोड़ दें। यह हमें बताता है कि मौजूदा संदर्भ में पार्टी ने खुद को जिस तरह संगठित किया है, जिस तरह वह चुनावों को देखती है, जिस तरह लोगों को जोड़ती है, उसमें कुछ न कुछ बुनियादी खामी है। मैं यह नहीं कह रहा कि संगठन का नेता कौन होना चाहिए, अकेली कांग्रेस पार्टी ही पूरा विपक्ष नहीं है। दूसरी पार्टियां भी हैं, तो उन्हें तय करने दीजिए कि कौन अगुआई करे, बजाए इसके कि कोई एक कहे कि अमुक अध्यक्ष होना चाहिए, मेरे टवीट में ग़लत क्या है।

प्रश्नः- कांग्रेस की अगुआई वाले यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) ने केन्द्र में 2004 से 2014 तक राज किया। इस तथ्य को देखते हुए पार्टी कह सकती है कि ये महज़ सत्ता-विरोधी नतीजों से जुए नुकसान थे, राहुल गांधी कह सकते हैं, देखो हमने मोदी लहर में भी चार राज्य जीते, यह कांग्रेस के उबरने का संकेत है, तो नेतृत्व पर हमला क्यों..?

उत्तरः- कांग्रेस का पतन कोई ताज़ा फेनोमेना नहीं है। आखिरी बार उसने 1984 में यह देख जीता था। (जब 404 सीटें जीतीं) 1984 के बाद पार्टी ने एक भी आम चुनाव नहीं जीता। हां, इस बीच उसने 15 साल राज किया, एक बार अल्पमत सरकार के रूप में और दो बार गठबंधन सरकार के रूप में। मगर पार्टी के रूप में उसने देश तो नहीं ही जीता। मसलन, 1989 के आम चुनाव में उसने महज़ 198 सीटें जीतकर सत्ता गंवाई। मगर 2004 में उसने केवल 145 सीटें जीतकर गठबंधन सरकार बनाई। तो सियासी पार्टी के तौर पर उसका पतन चिरकालिक है।

प्रश्नः- 2009 को छोड़ जब उसने 206 सीटें जीतीं थीं

उत्तरः- हां, लेकिन तब भी उसके पास अपने दम पर बहुमत नहीं था। उसके प्रदर्शन की बेहतर थाह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (से ली जा सकती) है। अपने शिखर पर कांग्रेस करीब 3500 निर्वाचन क्षेत्रों (फिलहाल कुल 4121 हैं) में नंबर 1 या करीबी पर नंबर 2 हुआ करती थी। आज यह संख्या घटकर 1500-1600 पर आ गई है। इसका ग्राफ गिरता रहा है, विशेषकर 1984 के बाद। कह मैं यह रहा हूं कि कांग्रेस की गिरावट तात्कालिक परिघटना नहीं है। यह किसी व्यक्ति या प्रसंग से जुड़ी नहीं है।

प्रश्नः- कांग्रेस में कई लोग ज़ोर देकर कहते हैं कि चूंकि आप पार्टी को रणनीति पर सलाह देने वाले थे और यह हो नहीं सका, इसलिए आप बदले की भावना से उन पर हमला कर रहे हैं..?

उत्तरः- देखिए, यह तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी बिन बुलाया मेहमान बनकर गांधी परिवार या कांग्रेस नेतृत्व के घर पहुंच जाए और कहे कि ज़रा मेरी रणनीति जान सुन लीजिए, उन्होंने मुझ से पूछा और मेरे विचार से जो ठीक लगा, वह मैंने बताया। अब मैंने जो उनके सामने पेश किया, उसे वे मानें या ख़ारिज कर दें। यह उनका अधिकार है। मुझे भी वह करने का अधिकार है जो सही है। कांग्रेस नेतृत्व के साथ मेरी पिछले दो वर्ष से बातचीत चल रही थी। बंगाल चुनाव के बाद यह कहीं ज़्यादा विधिवत, गहन बातचीत थी। मैं पार्टी में लगभग शामिल हो ही गया था, मगर कुछ मुद्दों पर हमें एहसास हुआ कि साथ आना दोनों ही पक्षों के लिए मददगार होने की बजाए नुकसानदायक होगा, हम ससम्मान अलग हो गए, कोई कटुता थी ही नहीं।

> **नेतृत्व के मुद्दे के अलावा उसे तेज़ी से फैसले लेने और स्थानीय नेताओं को ताक़तवर बनाने की ज़रूरत है। तमाम फैसले लेने को केन्द्रीयकृत करके दिल्ली में कुछेक व्यक्तियों के हाथ में सीमित रखने की ज़रूरत नहीं है। भारत इतना बड़ा और इतना विशाल है कि सारा ज्ञान और विशेषज्ञता कुछेक व्यक्तियों में ही समाई हो, यह मुमकिन नहीं है।**

प्रश्नः- कांग्रेस को क्या करना चाहिए?

उत्तरः- कांग्रेस पार्टी के तौर पर जिस तरह ढली है, जिस तरह वह काम करती है और जिस तरह वह फैसले लेती है, उसे बदलने की ज़रूरत है। आपको एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के आकार, पैमाने और विरासत वाली राजनैतिक पार्टी पिछले तीन वर्ष से अंतरिम अध्यक्ष या कामचलाऊ व्यवस्था के साथ काम कर रही है। क्या यह स्मार्ट क़दम है? सलाह के लिए आपको प्रशांत किशोर या उस लिहाज़ से किसी की भी ज़रूरत नहीं। आप जिसे भी चुनें, पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए।

प्रश्नः- और कोई मश्वरे.?

उत्तरः- नेतृत्व के मुद्दे के अलावा उसे तेज़ी से फैसले लेने और स्थानीय नेताओं को ताक़तवर बनाने की ज़रूरत है। तमाम फैसले लेने को केन्द्रीयकृत करके दिल्ली में कुछेक व्यक्तियों के हाथ में सीमित रखने की ज़रूरत नहीं है। भारत इतना बड़ा और इतना विशाल है कि सारा ज्ञान और विशेषज्ञता कुछेक व्यक्तियों में ही समाई हो, यह मुमकिन नहीं है। अगर आप कांग्रेस के शिखर वाले दिनों को देखें तो पाएंगे कि दिल्ली में बैठे चंद महासचिव उसे नहीं चला रहे थे। पार्टी मज़बूत थी क्योंकि उसके पास धाकड़ क्षेत्रीय नेता थे। मैं यह नहीं कह रहा कि उसके पास मज़बूत नेता नहीं, पर फिलहाल कांग्रेस जिस तरह काम करती है, उसे देखते हुए तो असल ताक़त महासचिवों में और जिसे लोग पार्टी आलाकमान कहते हें उसी में समाई है। बिल्कुल ज़मीनी स्तर से कांग्रेस के पुनरुत्थान में यही सबसे बड़ा रोड़ा है।

प्रश्नः- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल में ऐलान किया कि यूपीए मर चुका है और यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और विशेषकर राहुल गांधी पर हमला किया, यह कहकर कि नेता इतना सारा समय विदेश में नहीं बिता सकते..?

उत्तरः- वे ही बता सकती हैं कि उनका आशय क्या था, पर यह तर्कसंगत है क्योंकि यूपीए केन्द्र में सरकार बनाने और चलाने के लिए 2004 में बना था। यह उस स्थिति में राजनैतिक गठबंधन बनाने जैसी बात नहीं थी जब आप सरकार में न हों। अगर आप मान भी लें कि यह दोनों स्थितियों के लिए था, तो इसके गठन, इसके कामकाज पर नए सिरे से विचार का समय आ गया है क्योंकि इसके घटक दल बदल गए हैं, इसका हिस्सा रहे कई बदल बाहर चले गए हैं डायनैमिक्स बदल गया है तो आप वही यूपीए नहीं रख सकते जो 2004 में था। आप कहते रहें कि वही संगठन, उन्हीं समर्थकों और उसी कामकाजी तंत्र के साथ मौजूद है। यूपीए और उसके गठन पर नए सिरे से विचार की आवश्यकता है।

प्रश्नः- आपके यह भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व किसी का दैवीय अधिकार नहीं है। साफ है कि आप उसके वंशवादी झुकाव का ज़िक्र कर रहे थे..?

उत्तरः- नहीं, यह किसी व्यक्ति की ओर निर्देशित नहीं था। मेरी बात सीधी-सादी है, राजनैतिक पार्टी का नेता होने के नाते अब आप उसकी जीत का श्रेय लेते हैं तो दुनियाभर में लोकतांत्रिक पार्टी की नीति यह है कि जब आप हारते हैं तो पद छोड़ देते हैं और किसी दूसरे को नेतृत्व संभालने देते हैं। आप जितने चाहे मौक़े ले सकते हैं पर अगर किसी वजह से यह कारगर नहीं हो रहा, तो यही समय है कि आप

बाक़ी पेज 06 पर

चुनाव आते ही क्यों आने लगी मथुरा की याद

चुनाव के ठीक पहले सियासी मैदान के शूरमाओं की ओर से बयान आएं तो उनके राजनीतिक अर्थ निकाले ही जाएंगे। अगर बयान आबादी के लिहाज़ से सबसे बड़े और राजनीति के हिसाब से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा हो तो उसका विश्लेषण कुछ ज़्यादा ही होगा। यहां प्रसंग उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस टवीट का है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण का काम जारी है, मथुरा की तैयारी है।' याद किया जा सकता है कि वर्ष 2003 के राजस्थान, छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों में भाजपा ने एक नई परिपाटी डालने की कोशिश की थी। तब केन्द्र में वाजपेयी सरकार की अगुआई वाली सरकार थी। उस समय भाजपा के चुनावी रणनीतिकार प्रमोद महाजन ने तीनों राज्यों के चुनावों के लिए 'बीएसपी' को मुद्दा बताया था। बीएसपी यानि बिजली, सड़क और पानी।

साफ शब्दों में कहें तो भाजपा ने 18 वर्ष पहले चुनावी राजनीति के लिए विकास के मुद्दे को पहले पायदान पर रखना शुरू किया था। वर्ष 2014 और 2019 के संसदीय चुनावों में नरेन्द्र मोदी ने भी विकास को सबसे ऊपर रखा था। हालांकि भाजपा के अब तक के उभार में राम मंदिर आंदोलन की भी बड़ी भूमिका रही है। हर चुनाव में कमोबेश वह इस मुद्दे के इर्द-गिर्द रहती भी आई हैं लेकिन हाल के कुछ चुनावों में भाजपा ने प्रमुखता से सिर्फ विकास का मुद्दा उठाया है हिन्दुत्व और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों को उसने उसके बाद ही रखा है। यही वजह है केशव प्रसाद मौर्य ने जब मथुरा का मुद्दा उठाया तो उसके पीछे के अर्थ तलाशे जाने लगे। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से अब तक योगी आदित्यनाथ ने राजनीति की दुनिया में लंबी यात्रा तय की है। धीरे-धीरे वह भाजपा की राजनीति के केन्द्र में आते जा रहे हैं। हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी आलाकमान ने उनके हाथों राजनीतिक प्रस्ताव पेश करवाकर एक तरह से उनकी अहमियत को ही स्थापित करने की कोशिश की है। इन सबके बावजूद एक सच यह भी है कि वर्ष 2017 की उत्तर प्रदेश की जीत के एक स्तंभ केशव प्रसाद मौर्य भी रहे। उन दिनों पार्टी के वही अध्यक्ष थे। इस नाते मुख्यमंत्री पर उनकी निगाह भी रही ही होगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वह पिछड़ गए। बेशक उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में उन्हें नंबर दो का पद हासिल हुआ है, लेकिन शायद उनकी उम्मीदें बरकरार हैं।

कुछ राजनीतिक जानकार मौजूदा दौर को हिन्दुत्व का नवजागरण काल मानते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ख़ान कहते रहे हैं कि बहुसंख्यक वैचारिकी के उभार की वजह अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति रही है। नैरेटिव केन्द्रित राजनीति का भी हिन्दुत्व दर्शन और विचार की बुनियाद को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण योगदान है। केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक यात्रा विश्व हिन्दू परिषद् के दिग्गज अशोक सिंघल की छत्रछाया में शुरू हुई और आगे बढ़ी। इसलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मौर्य इन तथ्यों को अच्छी तरह समझते होंगे। मण्डल आयोग के बाद राजनीति जिस तरह पिछड़ावाद की ओर उन्मुख हुई है, उसकी वजह से विभिन्न दलों में स्वाभाविक रूप से पिछड़े वर्गों से राजनीतिक नेतृत्व उभरा। कई दलों ने सायास तरीके से भी पिछडे वर्ग के नेतृत्व को उभाने की कोशिश की। इस प्रक्रिया से भाजपा भी अलग नहीं है। इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखता है। ग़ैर यादव पिछड़ी जातियों में भाजपा की गहरी पैठ इसका ठोस उदाहरण है। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। इसलिए अगर चुनाव बाद के नए समीकरणों में उन्हें अपने लिए अवसर दिखता है तो उसमें कुछ असामान्य भी नहीं है।

बेशक अभी तक उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति में योगी आदित्यनाथ के लिए कोई चुनौती नज़र नहीं आती। लेकिन भाजपा में ही असम का भी उदाहरण है। तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल की ही अगुआई में पार्टी की असम में जीत हुई लेकिन चुनाव बाद उनकी जगह हिमंता बिस्वा सर्मा को कमान मिल गई। कुछ राजनीतिक समीक्षक इस संदर्भ में भी केशव प्रसाद मौर्य के टवीट को देख रहे हैं। हालांकि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1991 का पूजास्थल कानून अब भी बरक़रार है, जो कहता है कि आज़ादी के समय देश के पूजास्थलों की धार्मिक अवस्थिति थी, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अयोध्या के रामजन्मभूमि मंदिर को अपवाद माना गया है। ऐसे में मौर्य के बयान पर स्वाभाविक ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शासन में ज़िम्मेदारी के पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है।

यह भी सच है कि राम मंदिर आंदोलन के उभार के काशी और मथुरा के भी मामलों का ज़िक्र करता रहा हे। इसलिए यह मान लेना कि संघ विचार परिवार की राजनीति इससे इतर हो जाएगी, नादानी ही कही जाएगी। वैसे भी भाजपा के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो अक्सरहां उससे उन मुद्दों पर राय जानने की कोशिश करता रहा है। पार्टी को इन मुद्दों को उठाने की एक वजह भाजपा के लिए अपने प्रतिबद्ध वोटरों के रुझान को अभिव्यक्ति देना तो है ही, मौजूदा राजनति में खुद प्रासंगिक बने रहना भी है। अपने कोर वोटरों को जोड़े रखने के लिए जहां ऐसे कोर मुद्दों पर भाजपा को बने रहना होगा, वहीं विकास के मुद्दे पर भी आक्रामक राजनीति करनी होगी। केशव प्रसाद मौर्य के हालिया टवीट को इन तथ्यों के संदर्भ में समग्रता से देखा जाना चाहिए। ◘◘

रोज़गार ....

'रबर' उद्योग में अनेक अवसर

अच्छी नौकरी हर किसी को मिल ही जाए यह कोई पक्का नहीं, ग्रेजुएट हो या कम पढ़ा लिखा, या औसत सबको अपने अनुसार नौकरी मिलना मुमकिन नहीं, कई बार लोगों को कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मतलब जो काम वह नहीं करना चाहते वह उनको करना पड़ता है, जिस स्तर की शिक्षा उन्होंने ली है उस स्तर का काम नहीं चाह कर भी करना पड़ता है क्योंकि नौकरी की भारत एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, विशेषकर लॉकडाउन के बाद से। पर वह लोग जो अपना कारोबान कर रहे हैं उनको इस स्थिति से नहीं गुज़रना पड़ता। ऐसा ही एक कारोबार है ''रबर'' उद्योग। रबर के इस्तेमाल की यदि बात की जाए तो टायर-ट्यूब का ही ध्यान आता है। पर सच तो यही है कि रबर हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। टायर-ट्यूब के अलावा सैकड़ों ऐसे उत्पाद हैं, जिनके निर्माण में रबर का इस्तेमाल होता है। इनमें दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के अलावा विभिन्न औद्योगिक उपकरण भी शामिल हैं। यही वजह है कि इसके प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी है, जिनका काम रबर की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करने के अलावा इसके इस्तेमाल को और व्यापक बनाना होता है।

कैसे-कैसे कोर्स

रबर टेक्नोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जिससे संबंधित कोर्स विभिन्न विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं। बैचलर और मास्टर, दोनों ही स्तरों पर इससे संबंधित कोर्स में दाख़िला लिया जा सकता है। इसके तहत प्राकृतिक रबर के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। साथ ही सिंथेटिक रबड़ के निर्माण और उसके रखरखाव के बारे में भी बताया जाता है। रबर की गुणवत्ता और इसकी उपयोगिता को कैसे बढ़ाया जाए, इस संबंध में भी कोर्स में बताया जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में शोध के मौक़े भी मिलते हैं।

योग्यता क्या हो

साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास विद्यार्थी, रबर टेक्नोलॉजी से संबंधित बीई/बीटेक कोर्स में दाखि़ला ले सकते हैं। बीटेक के बाद इस क्षेत्र में एमटेक की पढ़ाई भी की जा सकती है। इसके बाद रिसर्च से भी जुड़ा जा सकता है। अधिकांश अच्छे संस्थानों में ऐंट्रेंस टेस्ट के आधार पर बीटेक में दाख़िला दिया जाता है। ऐसे में इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए ज़रूरी है कि एंट्रेंस टेस्ट की अच्छी तैयारी की जाए।

अवसर कहाँ मिलेंगे

कोर्स करने के बाद अभ्यर्थियों को देश-विदेश में मौजूद विभिन्न कंपनियों में अवसर मिलते हैं। मलेशिया, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में अधिक अवसर उपलब्ध हैं। सबसे अधिक मौक़े टायर इंडस्ट्री में ही मिलते हैं। एमआरएफ, अपोलो, डनलप आदि कई रबर कंपनियां हैं जो अपने यहां रबर टेक्नोलॉजिस्ट को नियुक्त करती हैं। इसके अलावा रबर के विभिन्न उत्पाद बनाने वाली कंपनियों में भी अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां निकलती रहती हैं। जिस तरह रबर की उपयोगिता दिनोदिन बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में शोध-कार्य के लिए भी विशेषज्ञों की आवश्यकता बनी रहती हैं।

मुख्य संस्थान

इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर (पश्चिमी बंगाल)

कोर्स : एमटेक इन रबर टेक्नोलॉजी, अवधि : 2 साल

www.iitkgp.ac.in

गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद,

कोर्स: बैचरल ऑफ रबर इंजीनियरिंग, अवधि : 4 साल

www.gujratuniversity.org.in

महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोटटयम (केरल)

कोर्स : बैचलर ऑफ साइंस इन रबर टेक्नोलॉजी, अवधि : 3 साल

www.mguniversity.du

अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई (तमिलनाडु)

कोर्स : बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन रबर एण्ड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग

अवधि : 4 साल

www.annauniv.edu ◘◘

वार्ता से पहले ईरान की मांग, कच्चे तेल के आयात की मंज़ूरी दी जाए

तेहरान : परमाणु समझौता बहाल करने के लिए वियना में शुरू होने वाली वार्ता से पहले ईरान ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी तेहरान को ईरानी कच्चे तेल का निर्यात करने की अनुमति देने का वादा करें। ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान के बयान से संकेत मिलता है कि यह खाड़ी देश 2015 एटमी समझौता बहाल करने संबंधी अपना पक्ष मज़बूत करने की कोशिश में जुटा है। ईरान चाहता है कि आगामी दौर की वार्ता में इस बिन्दु पर पहुंचने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए कि ईरानी तेल आसानी से और बिना किसी रुकावट के बेचा जा सके और इसका धन ईरान के बैंक खातों में पहुंचे।

भ्रष्टाचार मामलों में सोमालिया के पीएम रोबल हटा गए

मोगादिशु : सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद फरमाजो ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को उनके पद से हटा दिया है। रोबल के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जारी है। फरमाओ ने कहा कि रोबल पर भ्रष्टाचार व सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग का भी आरोप हैं उन्होंने रोबल पर चुनावी प्रक्रिया को नाकाम बनाने का आरोप भी लगाया। फरमाजो ने कहा, रोबल के काम व शक्तियों को जांच होने तक निलंबित किया गया है और जगह महदी मोहम्मद गुलेद कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे।

म्यांमार की अदालत ने सू की के ख़िलाफ़ फैसला टला

बैंकॉक : सैन्य शासन से जूझ रहे म्यांमार में एक अदालत ने सत्ता से बेदख़ल की गई नेता आंग सान सू की के ख़िलाफ़ दो आरोपों पर अपना फैसला टाल दिया है। सू की पर आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना वॉकी टॉकी रखने और उनका आयात करने का आरोप है।

भ्रष्टाचार से नहीं निपट रही पाक: मंत्री

कराची: पाक में इमरान ख़ान सरकार के बड़बोले मंत्री शेख राशिद ने इस बार अपने ही प्रधानमंत्री की मुश्किलों को बढ़ाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार भ्रष्टाचार से निपटने में नाकाम रही है। राशिद का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां संघीय सरकार के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लगातार हमलावर हो रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि इमरान सरकार की ग़लत नीतियों के चलते देश में भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है।

कांग्रेस ही अकेली विपक्षी पार्टी है

जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुक़ाबला कर रही है

किसी और को मौक़ा लेने दें। इस लिहाज़ से राजनैतिक पार्टी ही क्यों, किसी कॉपोरेट, किसी भी संस्था, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान या किसी भी टीम को लीजिए, अगर नेता लगातार नाकाम हो रहा है, तो क्या यह तर्कसंगत नहीं है कि वह अलग हट जाए और किसी और को वह काम करने दे? वह 'कोई और' भी कांग्रेस से हो सकता है।

प्रश्नः-राहुल गांधी हट तो गए थे?

उत्तरः- मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस नेतृत्व की बात कर रहा हूं जिसके मातहत पिछले 10 वर्ष से चुनाव लड़े जाते रहे हैं वह नेतृत्व 90 फीसदी चुनावो में नाकाम हो चुका है और यह कड़वा सच है। जब जो भी नेता था, नैतिकता और रणनीतिक बोध का तक़ाज़ा है कि आप हट जाएं और किसी को और (कमान) संभालने दें।

प्रश्नः- क्या आप वंशवादी उत्तराधिकारी के ख़िलाफ़ हैं?

उत्तरः- वंशवाद इस देश की सच्चाई है। हम में से कइयों को हय दुर्भाग्यपूर्ण लग सकता है, पर यह सच है। डेटा बताता है कि मौजूदा संसद में या पिछली सांसदों में 40 से कम आयु के दो तिहाई सांसदों का किसी न किसी प्रकार का ख़ानदानी संबंध था। जब चुनावी राजनीति की बात आती है, जिन लोगों की वंशवादी पृष्ठभूमि नहीं है, उनका प्रवेश लगातार मुश्किल होता जा रहा है। मगर यह लंबे वक्त की चुनौती है जिसका मुक़ाबला भारतीय लोकतंत्र को करना होगा। यह आदर्श नहीं है, पर हम चाहने भर से इससे छुटकारा नहीं पा सकते। हालांकि इसके लिए ज़्यादातर कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है पर गलती ज़्यादा नहीं तो बराबर से दूसरी पार्टियों की भी है। पर ये ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी।

प्रश्नः- आप ममता बनर्जी को सलाह दे रहे हैं?

उत्तरः- नहीं, मैं ममता बनर्जी को सलाह नहीं दे रहा। मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद मैं जो कर रहा था, वह छोड़ दूंगा। मैं जिस संगइन आइ-पीएसी (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) में काम किया करता था, अगर आप जाकर देखें तो बीते छह माह में उनके दफ्तरों में बमुश्किल 2-3 बार गया होऊंगा। मेरी इच्छा है कि हम एक ऐसा राजनैतिक तानाबाना जुड़ता देख सकें जो असरदार हो, जो उस 60 फीसद जगह को मज़बूत करता हो जो गद्दीनशीन निज़ाम के साथ नहीं है। इसी के लिए मैं लोगों से मिलता हूं लेकिन मोटे तौर पर मैं घर बैठा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं।

प्रश्नः- ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक को तैयार करती मालूम देती हैं। क्या तृणमूल में वंशवादी उत्तराधिकारी चल रहा है?

उत्तरः- तृणमूल की कमान और कंट्रोल 100 प्रतिशत ममता बनर्जी के हाथ में है। वे खुद काम करने वाली नेता हैं। ममता बनर्जी ही शो चला रही थीं और चला रही हैं। अभिषेक बनर्जी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं।

प्रश्नः- अभिषेक बनर्जी की विशेषताएं और भागीदारी क्या है..?

उत्तरः- यह तय करना पार्टी का काम है, पर वे तीसरी बार सांसद हैं और मैं मानता हूं कि वे पार्टी को मज़बूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर घोषित उनकी भूमिका बंगाल के बाहर तृणमूल के विस्तार में मदद करना है।

> **वंशवाद इस देश की सच्चाई है। हम में से कइयों को हय दुर्भाग्यपूर्ण लग सकता है, पर यह सच है। डेटा बताता है कि मौजूदा संसद में या पिछली सांसदों में 40 से कम आयु के दो तिहाई सांसदों का किसी न किसी प्रकार का ख़ानदानी संबंध था। जब चुनावी राजनीति की बात आती है, जिन लोगों की वंशवादी पृष्ठभूमि नहीं है, उनका प्रवेश लगातार मुश्किल होता जा रहा है। मगर यह लंबे वक्त की चुनौती है जिसका मुक़ाबला भारतीय लोकतंत्र को करना होगा। यह आदर्श नहीं है, पर हम चाहने भर से इससे छुटकारा नहीं पा सकते।**

प्रश्नः- वाक़ई ममता बनर्जी अपने पंख फैलाती मालूम दे रही हैं, तृणमूल गोवा, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। क्या तृणमूल नई कांग्रेस बनने की कोशिश कर रही है?

उत्तरः- यह तो समय ही बताएगा पर तृणमूल के तथाकथित विस्तार को कुछ ज़्यादा ही तूल दिया जा रहा है। तथ्य यह है कि इन राज्यों से लोकसभा की महज 4-5 सीटें आती हैं। बार-बार कहा जाता है कि कांग्रेस ही अकेली विपक्षी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुक़ाबला कर रही है लेकिन डेटा दूसरी ही तस्वीर दिखाता है। भाजपा के ख़िलाफ़ कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 2019 के लोकसभा चुनाव में महज़ 4 प्रतिशत और 2014 में 6 प्रतिशत था। जिन पर कांग्रेस ने भाजपा से सीधी लड़ाई लड़ी, ऐसी हर 100 सीटों में से उसने केवल चार सीटें जीतीं। उसकी जीत का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु, केरल, पंजाब में था, जहां उसका सामना भाजपा से नहीं था, हां वह भाजपा से लड़ रही है पर जीत कुछ पा रही। तो अगर कोई और विपक्षी पार्टी 15-20 सीटों के लिए कोशिश कर रही है तो इसमें ग़लत क्या है..?

प्रश्नः- ममता बनर्जी का गेमप्लान क्या है?

उत्तरः- यह तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर तृणमूल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और वाइएसआर कांग्रेस या वे जिनकी जड़ें कांग्रेस के विचार, जगह पर विचारधारा से आई हैं, साथ मिलकर कोशिश करें तो वे कांग्रेस के मौजूदा स्वरूप का संभावित विकल्प बनकर उभर सकती हैं। यह कांग्रेस के लिए नई परिघटना नहीं है उनके लंबे इतिहास में यह कम से कम 3-4 बार हो चुका है। 1969 में जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस (आइ) बनाई। यह ज़्यादा बड़ी कांग्रेस बनकर उभरी, सैद्धांतिक तौर पर यह संभावना मौजूद है कि कोई भी नई कांग्रेस बना सकता है अगर वह स्पेस ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप मौजूदा कांग्रेस में बदलाव आते देखेंगे।

प्रश्नः- हमारी समझ से ममता ऐसी विपक्षी एकता चाहेंगी जिसमें जो भी क्षेत्रीय पार्टी जहां मज़बूत है, मसलन तमिलनाडु में स्टालिन, आंध में जगन रेड्डी, तेलंगाना में केसीआर या फिर महाराष्ट्र में शरद पवार, वह उस राजय में बेरोकटोक लड़े। वे यह मानती लगती हैं कि इन इलाकों का कुल योग इतना बड़ा और संपूर्ण हो सकता है कि भाजपा को हरा सके?

उत्तरः- यह पूरी की पूरी धारणा कि हर कोई साथ आकर भाजपा को हराने के लिए बहुत मज़बूत विपक्ष बना देगा, सफल न होगी। असम में इस वर्ष राज्य के चुनाव में एक महागठबंधन था, वह हार गया। हम यूपी में यही देख चुके हैं, जहां बसपा-सपा और दूसरी पार्टियां 2017 में साथ आईं और हार गईं। तो हमें अतीत से सीखना पड़ेगा। महज़ कई पार्टियों का एक साथ आना मौजूदा भाजपा के ख़िलाफ़ सफलता के लिए पक्का उपाय नहीं है। उसके लिए आपको एकजुट करने वाले चेहरे की, नैरेटिव की और फिर समीकरण की दरकार होगी ताकि लोगों को एक संयुक्त विपक्ष दिखाई दे।

प्रश्नः- परिदृश्य पर क्या आपको ऐसा कोई नेता दिखाई देता है?

उत्तरः- नेता खोजने की यह क़वायद ग़ैर ज़रूरी है, फर्ज़ कीजिए कि हम यह इंटरव्यू 1972 में कर रहे हैं। अपनी पूरी अक़्लमंदी से क्या कोई यह भविष्यवाणी कर सकता था कि जेपी (जयप्रकाश नारायण) नाम का एक नेता विपक्ष को एकजुट करेगा और उसका चेहरा बन जाएगा? अगर हम यह बातचीत 1986 में कर रहे होते, तो भी क्या यह कहा जा सकता था कि वी.पी. सिंह चेहरा बन जाएंगे? 2010 में नरेन्द्र मोदी के बारे में किसने सोचा था? मोदी सरकार के लिए तीन बड़े यू-टर्न देखिए। पहला ज़मीन अधिग्रहण विधेयक था। क्या हम वह चेहरा याद कर सकते हैं जिसने उस विरोध की अगुआई की थी? नहीं। दूसरा नेशनल रजिस्टार ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) था, जिसे रद्द नहीं किया गया है, लेकिन उस क़दम आगे नहीं बढ़े हैं। क्या हम किसी नेता विशेष को याद कर सकते हैं जिसकी वजह से सरकार क़दम पीछे खींचने को मजबूर हुई? हाल में सरकार ने कृषि क़ानून रद्द कर दिए, लेकिन क्या हम किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जिसे इसका श्रेय दिया जा सके? मैं कह यह रहा हूं कि अगर आपके पास सही मुद्दे हैं, तो आप नैरेटिव खड़ा कीजिए, चेहरा उभर आएगा, तो यह पूरी बहस कि पहले चेहरे की पहचान की जाए और तब तक आपके पास कोई चैलेंजर नहीं हो सकता, आगे बढ़ने का सही तरीक़ा नहीं है।

प्रश्नः- लखीमपुर खीरी में कांग्रेस के किसान आंदोलन के बाद आपने कहा कि आसान और फौरी समाधान काम नहीं आएंगे?

उत्तरः- देश के तौर पर हम टी-20 मोड में आ गए लगते हैं, सब कुछ दिन में तय होना है, हर चीज पर हां या नहीं होना है, व्हाटसऐप यूनिवर्सिटी जहां सब कुछ

बाक़ी पेज 07 पर

यह ज़रूरी नहीं कि यूपी चुनाव के नतीजों में यह झलक मिले कि
2024 के आम चुनावों में क्या होगा

एक लाइन में कहा जाना चाहिए, बारीक और ब्योरेवार तर्क- वितर्क की कोई जगह ही नहीं है। आप या तो मोदी भक्त हैं या राहुल गांधी भक्त। यह सोच विपक्ष को चोट पहुंचाती और कमज़ोर करती है। कुछ चुनौतियां बड़ी और जटिल हैं और आपको तफसील से समझना होता है, ऐसे तर्क और स्थापनाएं करनी होती हैं जिनकी कई परतें हैं, वे महज़ बाइनरी नहीं।

प्रश्न:- फिर कांग्रेस पर लौटें, क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गाँधी पराजित सेनानायक हैं और उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए?

उत्तर:- हम उन अकेले को पराजित सेनानायक नहीं कह सकते, क्योंकि हर लिहाज़ से नेतृत्व मिला जुला है जिसमें मौजूदा अध्यक्ष और वे इसे चला रहे हैं। मुझे इसे सही नज़रिए से रखने दीजिए, मैं सोनिया गांधी के मातहत कांग्रेस का रिकॉर्ड इसलिए देखता हूं क्योंकि वे 25 साल इसकी प्रमुख रहने के साथ लंबे समय रहने वाली कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उनका चुनावी स्ट्राइक रेट कोई 31-32 के आसपास आता है, यानि कांग्रेस ने जितने चुनाव लड़े उनके एक तिहाई, बतौर राहुल अध्यक्ष का स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करीब 34-35 प्रतिशत था। दोनों का कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। मगर 2019 से, जब किसी को पता नहीं कि नेता कौन है, स्ट्राइक रेट घटकर 10 प्रतिशत या इससे भी नीचे आ गया है। आपको इसे भी देखने की ज़रूरत है।

प्रश्न:- आपको लगता है कि गांधी परिवार को अब जाना चाहिए?

उत्तर:- नहीं, मैं यह नहीं कह रहा, ज़रूरत इसकी संरचना बदलने की है। मुमकिन है आप अपनी जगह सही हों पर कभी-कभी बनावट का विन्यास या व्यवस्था बदलकर आप बेहतर काम कर सकते हैं क्योंकि मौजूदा बनावट निश्चित रूप से कारगर नहीं। मौजूदा बनावट और संगठन के स्वरूप को देखते हुए अगले कुछ सालों में भाजपा के ख़िलाफ़ इसके कोई बड़ी चुनावी सफलता हासिल करने की संभावना कम ही है। मैं कांग्रेस ही नहीं, व्यापक यूपीए की बनावट की बात भी कर रहा हूं।

प्रश्न:- नेतृत्व का प्रश्न अलग रख दें, तब तो यह तथ्य तो है कि कांग्रेस बड़ी विपक्षी ताक़त है। क्या आप किसी भी विपक्षी गठबंधन को ग्रैंड ओल्ड पार्टी को अनदेखा करने की सलाह देंगे..?

उत्तर:- कांग्रेस से जिस विचार और स्पेस का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद की जाती थी और जिस पर वह काबिज़ है, ज़मीन पर वह अब भी मज़बूत है। प्रश्न यह है कि आप इसे साथ लाकर चुनावी सफलता में कैसे बदलते हैं। मेरा तो पक्के तौर पर मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तीसरी पार्टी के लिए सही मायने में भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में आ पाने की कोई गुंजाइश नहीं। जब तक कि आप वह जगह नहीं लेते जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। पर मैं यह भी कह रहा हूं कि आपको भिन्न समीकरण की ज़रूरत है।

प्रश्न:- आपने हाल ही में कहा था कि भाजपा बहुत ज़्यादा मज़बूत ताक़त है और उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता, क्यों..?

उत्तर:- राजनैतिक ताक़त के रूप में भाजपा को आप बस चाहकर नहीं हटा सकते। पहले आपको देखना होगा कि उन्हें यहां तक कौन सी चीज लेकर आई है। पिछले 50-60 सालों में कई पीढ़ियों के लिए किए गए कामों के नतीजतन बना पुराना संगठन है जो जनसंघ और उससे भी पहले शुरू हुआ था, अब 60-70 सालों के संघर्ष के बाद वे 30-35 प्रतिशत वोट तक पहुंचे हैं। मुमकिन है कि वे एक या कि कई चुनाव हार जाएं, पर अगर अखिल भारतीय स्तर पर 30 प्रतिशत वोट पाने वाला विशाल संगठन एक बार खड़ा हो चुका है तो वह राजनैतिक संगठन आपके चाहने भरे से दूर नहीं बिठाया जा सकता।

प्रश्न:- तृणमूल के हाथों भाजपा की हार का सबसे बड़ा पाठ क्या था?

उत्तर:- यह कि आप रक्षात्मक नहीं रह सकते, आप बहुत देर से अभियान नहीं शुरू कर सकते, और यह कि आप मुतमईन नहीं रह सकते, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ, तृणमूल को उसे स्वीकारना पड़ा क्योंकि वह शायद यह मानने को तैयार न थी कि भाजपा बंगाल में मज़बूत ताक़त बन गई है। अगर आप प्रतिद्वंदी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो उसकी ताक़त को स्वीकार करने में कोई समस्या न होगी। आपको पता रहेगा कि उसे किस तरह से हराना है।

प्रश्न:- ममता बनर्जी ने भाजपा के ध्रुवीकरण के दांव का मुक़ाबला कैसे किया?

उत्तर:- ध्रुवीकरण एक पहलू था और इसी वजह से भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 38 प्रतिशत वोट हासिल किया। इसमें से बड़ा हिस्सा धार्मिक आधार पर हुए ध्रुवीकरण से आया। लेकिन ध्रुवीकरण की भी अपनी सीमाएं हैं। हमने आंकड़ों पर नज़र डाली और पाया कि ध्रुवीकरण 50-55 प्रतिशत तक सीमित है। धार्मिक आधार पर किसी भी समुदाय का ध्रुवीकरण 50-55 से ज़्यादा नहीं कर सकते। बंगाल में मोटे तौर पर ऐसा ही हुआ।

कथित तौर पर लहर वाले चुनावों में, मसलन 1984 में इंदिरा जी की मौत के बाद की परिस्थितियों में, जाति के बंधन टूट गए थे। 2014 में नरेन्द्र मोदी ने भारत की सोच को साध लिया और जागति बंधन तोड़ दिए थी। इसी तरह वीपी सिंह के समय राजा नहीं फकीर है, देश के तकदीर है या भ्रष्टाचार-विरोधी योद्धा के रूप में नैरेटिव गढ़े जाने पर भी जातिगत कारक बेअसर हो गए थे। किसी लोकप्रिय चेहरे या नैरेटिव या फिर घटना की ग़ैर मौजूदगी में लोग अपनी पहचान तक सिमट जाते हैं। चलो कुछ नहीं तो अपनी जाति वाले को (वोट) दे देते हैं।

प्रश्न:- तब क्या आप कहेंगे कि हिन्दुत्व की अपनी सीमाएं हैं, जिसे भाजपा और आरएसएस एक चुनावी रणनीति के रूप में प्रचारित कर रहे है?

उत्तर:- दरअसल, किसी भी रणनीति की अपनी सीमाएं होती हैं, उस हद तक, हिन्दुत्व की भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि हिन्दू कोई एक ही जैसे लोगों का धार्मिक समुदाय तो है नहीं। भले तमाम लोग ऐसा ही मानते हों, दूसरी बात, मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर 50 प्रतिशत हिन्दू ऐसे हैं जो हिन्दुत्व के आधार पर भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। इसकी पुष्टि आंकड़े भी करते हैं जो बताते है। कि भाजपा को वोट देने वाले हर हिन्दू पर एक अन्य हिन्दू भी होगा जो भाजपा को वोट नहीं करेगा। भाजपा को सियासी चुनौती देने वाली कोई भी पार्टी उसी दूसरी आधी हिन्दू आबादी पर नज़र गड़ाएगी और चुनावी रूप से भाजपा से मुक़ाबला करने के लिए उसे पक्ष में करने की कोशिश करेगी।

प्रश्न:-फरवरी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, वहां ध्रुवीकरण किस तरह काम करेगा, खासकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिन्दुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं?

उत्तर:- ध्रुवीकरण का चेहरा चाहे जो भी हो या ध्रुवीकरण की घटना कोई भी हो, इसकी सीमाएं होंगी ही। मैं कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता, इसलिए इस बारे में बात करने की बजाए कि यूपी में चुनावी नतीजे क्या होंगे, मैं एक ठोस बिन्दु सामने रखना चाहता हूं, यह ज़रूरी नहीं कि यूपी चुनाव के नतीजों में यह झलक मिले कि 2024 के आम चुनावों में क्या होगा। कई सारे लोग इसी जाल में फंस रहे हैं कि यूपी के नतीजे 2024 का रुख़ तय करेंगे। मैं आंकड़ों से इसे ग़लत साबित करूंगा। 2012 में भाजपा यूपी में तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी थी। समाजवादी पार्टी ने वह चुनाव जीत लिया था, लेकिन 2014 के आम चुनाव में उसका कोई असर नहीं पड़ा। अगर वह सच था तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि 2022 में जो होगा वहीं, 2024 में भी होगा। 2024 के पहले कई दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं।

प्रश्न:- चुनाव नतीजे तय करने में जाति आधारित राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है?

उत्तर:- जाति बहुत महत्वपूर्ण है, पर मतदान के समय जाति को कितनी तवज्जोह मिलती है, यह बहस का विषय है। मेरी समझ से, कोई पॉपुलर चेहरा या वैसा कोई मुद्दा या फिर कोई भावनात्मक पहलू न होने की स्थिति में ही जाति भूमिका निभाती है। कथित तौर पर लहर वाले चुनावों में, मसलन 1984 में इंदिरा जी की मौत के बाद की परिस्थितियों में, जाति के बंधन टूट गए थे। 2014 में नरेन्द्र मोदी ने भारत की सोच को साध लिया और जागति बंधन तोड़ दिए थी। इसी तरह वीपी सिंह के समय राजा नहीं फकीर है, देश के तकदीर है या भ्रष्टाचार-विरोधी योद्धा के रूप में नैरेटिव गढ़े जाने पर भी जातिगत कारक बेअसर हो गए थे। किसी लोकप्रिय चेहरे या नैरेटिव या फिर घटना की ग़ैर मौजूदगी में लोग अपनी पहचान तक सिमट जाते हैं। चलो कुछ नहीं तो अपनी जाति वाले को

बाक़ी पेज 11 पर

ख़ास ख़बरें

श्रीलंका : बिना एनओसी शादी नहीं रचा सकेंगे विदेशी

कोलंबो : श्रीलंका में किसी भी विदेशी को शादी करने के लिए अब रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना ज़रूरी होगा। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने इसे 1 जनवरी 2022 से अनिवार्य कर दिया है। श्रीलंकाई सरकार के इस फैसले की विपक्ष और कई सिविल समूह आलोचना कर रहे हैं। रजिस्ट्रार जनरल वीरासेकेरा ने एक सर्कुलर में कहा कि इस तरह की शादी का पंजीकरण, विदेशी नागरिक को सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से कराना होगा।

अमेरिका करेगा रूस से वार्ता

मॉस्को : रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि नाटो के यूक्रेन एक विस्तार पर रोक लगाने को लेकर पश्चिमी देशों से गारंटी की मांग पर अमेरिका के साथ उनके देश की वार्ता नए वर्ष में शुरू होगी। उन्होंने कहा हम मुख्य वार्ता अमेरिका के साथ करेंगे। रूस में दस दिनों की छुट्टिया 9 जनवरी को खत्म होंगी। पिछले दिनों रूस ने सुरक्षा दस्तावेज़ों का एक मसौदा सौंप मांग की थी कि नाटो यूक्रेन और पूर्व अन्य सोवियत देशों को सदस्यता देने से मना करे और वह मध्य एवं पूर्वी यूरोप से अपने सैनिकों को वापस बुलाए।

जलियांवाला बाग कांड का बदला लेने वाला सिख गिफ्तार

लंदन : सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक नकाबपोश 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए महारानी एलिजाबेथ की हत्या करने का ऐलान कर रहा है। इसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने जांच शुरू की और घुसपैठिए को विंडसर कैसल (महारानी के निजी आवास) के पास से गिरफ्तार कर लिया। यह नकाबपोश खुश की पहचान भारतीय सिख जसवंत सिंह चैल के रूप में बता रहा है।

नेपाल : चीन को झटके की तैयारी देउबा ने 'एमसीसी' पर दिया ज़ोर

काठमांडो : नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने भारत दौरे से ठीक पहले चीन को एक बड़ा झटका देते हुए सभी सियासी दलों से सहमति बनाकर 'मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन' (एमसीसी) के तहत प्रस्तावित अमेरिकी अनुदान मदद की पुष्टि करने को कहा है। उनका बयान ऐसे वक़्त में आया है जब चीन यहां अपने प्रोजेक्ट लाने को आतुर हे। दोबव ने कहा, एमसीसी के तहत 50 करोड़ डॉलर के कार्यक्रम राष्ट्रीय हित के ख़िलाफ़ नहीं है।

अल्लाह तआला को राज़ी करने के लिए कोई चीज़ छोड़ोगे तो वह तुम्हें उसके बदले में इससे बेहतर चीज़ इनायत फरमाएगा (1)

अल्लाह तआला का इरशाद है (अनुवाद) 'यानि जो शख़्स अल्लाह तआला से डरता है अल्लाह उस के लिए हर तंगी से रास्ता निकाल देता है और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता है। इसी तरह एक सही हदीस में आया है जिसको इमाम अहमद बिन हंबल (रह0) ने अपनी मसनद में रिवायत किया है कि हज़रत अबू कतादा और हज़रत अबू अल धमा फरमाते हैं कि हम एक बदवी सहाबी के पास आए और अर्ज़ किया कि क्या आपने हुज़ूर (सल्ल॰) से कोई बात सुनी है? उन्होंने फरमाया कि हां मैंने आप (सल्ल॰) से यह इरशाद सुना है, अनुवाद 'यानि अगर तुम अल्लाह तआला को राज़ी करने के लिए कोई चीज़ छोड़ोगे तो अल्लाह तआला तुम्हें उसके बदले में इससे बेहतर चीज़ इनायत फरमाएगा।

फितनों से लबरेज़ इस दुनिया में जिसमें इंसान के सामने तरह तरह की फितना सामानियां, दिल फरेबियां और रानाइयां ज़ाहिर होती हैं और इसको सिराते मुस्तक़ीम से हटाने की कोशिश करती हैं, मर्द मोमिन के लिए यह आयत करीमा और यह हदीस शरीफ़ नींव का पत्थर साबित होती है, इनके अर्थों में ग़ौर करने से इसको सीधे मार्ग पर क़ायम रहने में बड़ी मदद हासिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला का यह वादा कि तक़वा से अल्लाह ताआला फतह व नुसरत और ख़ैरों बरकत के दरवाज़े खोल देता है और जो शख़्स अल्लाह ताअला की रज़ा जूई के लिए हराम और बुरे से बचता है तो अल्लाह तआला उसको हलाल और सही तरीक़े से वही चीज़ बल्कि उससे बड़ी बेहतर चीज़ इनायत फरमाता है। यह वादा अनेक बार दुनिया में अल्लाह के बंदों को स्पष्ट तौर पर पूरा होता हुआ नज़र आता है। असंख्य वाकेआत हैं जो उसकी मुजस्सिम तफ़्सीर और अमली तशरीह हैं, इस तरह के दो वाक़ए शेख़ अली तन्तावी (रह॰) ने लिखे हैं (जो उन की किताब में मौजूद हैं) यह दोनों वाक्ये अपने अंदर इबरत व नसीहत का बड़ा सामान और अज़ीम पैग़ाम रखते हैं। शेख़ तनतावी ने दोबारा ताकीद से फरमाया है कि यह दोनों वाक्य हकीक़ी हैं ख़्याली नहीं हैं और जिन लोगों के साथ वह पेश आए हैं मैं इनसे परिचित हूं। पहला वाक्या दमिश्क की खूबसूरत मस्जिद जामअ अल तूबा का है इसमें एक परहेज़गार बाअमल रब्बानी आलम शेख़ सलीम मसूती रहते थे, जो तालीम व तरबीयत का काम बड़ी हिकमत से अंजाम देते थे। मौहल्ले के सारे लोगों को उन पर बड़ा विश्वास था और दीनी व दुनियावी मामलों में वह मरजअ विचार थे इनकी तरबीअत में एक नेक और शरीफ़ तालिबे इल्म रहते थे। जो फकर व नादारी के साथ इज़्ज़ते नफ़्स और ग़ैरत व ख़ुद्दारी में जर्ब अल मिसल थे। वह मस्जिद के सटे भाग हुजरे में रहते थे। एक दिन इनको सख़्त फाक़ा (भूख) से दोचार होना पड़ा दो दिन तक कोई चीज़ खाने को उपलब्ध नहीं हुई, तीसरे दिन इनको ऐसा लगा कि अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो मौत का निवाला बन जाएंगे, और आख़िर अपने आप से फैसला किया कि मैं हद इज़्तरार में दाख़िल हो गया हूं और मेरे लिए ज़रूरत के अनुसार मुर्दार या हराम खाना जाइज़ हो गया है। मस्जिद के आसपास आबादी थी जिसके घर एक दूसरे से जुड़े थे, छतें आपस में मिली हुई थीं कि आसानी से आदमी एक घर की छत से दूसरे घर की छत पर जा सकता था, वह मस्जिद की छत पर चढ़े और वहां से एक निकट घर पर गए उसको नीचे औरतें नज़र आई वह नज़र झुका कर दूर हो गए और पड़ौस के दूसरे घर की छत पर गए जो ख़ाली नज़र आया और किसी चीज़ के पकने की खूश्बू आयी, भूख के आलम में इस खूश्बू ने उसके दिल के लिए मकनातीस का काम किया, दो चार छलांग में वह नीचे पहुंच गए। जल्दी से मतबख में दाख़िल हुए देग़ची का ढक्कन खोला तो इसमें बैगन का कोई पकवान देखा, उन्होंने एक बैगन निकाला, भूख की तेज़ी से इसके गरम होने की परवाह किए बग़ैर एक लुक़्मा उसमें से खाने का इरादा किया। लेकिन अचानक इन पर फिर एक कैफिअत तारी (छाई) हुई और अपने दिल में कहा ''असतग़फिरूल्लाह आऊज़ू बिल्लाह'! मैं तालिब इल्म हूं, मस्जिद के अंदर रहता हूं, फिर मैं घर के अंदर घुसकर चोरी करूं! वह अपने किए हुए पर बड़े नादिम हुए और तौबा व अस्तग़फार किया। बेंगन देगची में वापस रख दिया और लौट कर मस्जिद में आ गए और शेख़ के हलके में आ बैठे, भूख की वजह से हालत बताने वाली न थी, सबक़ पूरा होने के बाद लोग जब अपने-अपने घर चले गए और मस्जिद में सिर्फ शेख़ और यह तालिबे इल्म रह गए तो एक औरत परदे के साथ दाख़िल हुई और शेख़ से उस ने कुछ बातचीत की जो इस तालिब इल्म ने नहीं सुनीं। शेख़ ने इधर उधर नज़र दौड़ाई मस्जिद में इसके अलावा कोई नज़र नहीं आया तो उसको बुलाकर पूछा क्या तुम शादीशुदा हो? उसने जवाब दिया नहीं, शेख़ ने फरमाया शादी करोगे? तालिब इल्म ख़ामोश रहा, शेख़ ने दोबारा वही जुमला दोहराया तालिब इल्म बोला मेरे मख़्दूम व मोहतरम मेरे पास तो एक रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मैं शादी क्योंकर कर सकता हूं। शेख़ ने फरमाया इस औरत ने मुझे बताया कि इसके शौहर का इन्तेक़ाल हो गया है और यह इस शहर में अजनबी है, इसके औलिया व अज़ीज़ों में सिर्फ इसके बूढ़े चचा मौजूद हैं जिनको वह अपने साथ लाई है, वह मस्जिद के कोने में बैठे हैं इस ख़ातून ने अपने शौहर से विरासत में बड़ा माल व दौलत पाया है, अब इसकी इच्छा है कि वह हुक्म ख़ुदावंदी और सुन्नत नबवी (सल्ल.) के अनुसार किसी दीनदार मर्द से शादी करे ताकि तन्हा (अकेली) न रहे और बदमाश लोग उसके बारे में किसी प्रकार का लालच न करें। तो क्या तुम, उससे शादी करने के लिए तैयार हो? तालिब इल्म ने रज़ामंदी का इज़्हार किया, शेख़ ने औरत से पूछा तुम इस तालिब इल्म से शादी करने पर राज़ी हो? उसने हां में जवाब दिया।

(शेष अगले अंक में)

गाने की आवाज़ से आप पर नींद तारी हो जाना

हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा मैं बकरियाँ चराने गया हुआ था, मैंने अपने साथी से कहा कि मैं मजलिस में देख कर आता हूँ क्या हो रहा है तुम मेरी बकरियाँ संभालो, नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ ले आए तो देखा कि गाने की आवाज़ आ रही है, आप ने मालूम किया कि क्या हो रहा है? बतलाया गया कि शादी हो रही है, जैसे ही गाने की आवाज़ आप के कान में पड़ी, तो अल्लाह तआला ने आप पर नींद तारी फ़रमा दी, पूरी रात आप सोते रहे ताआँकि जब सूरज तुलू हो गया तब बेदार हुए ताकि आप के कान में गाने की आवाज़ न आ सके। अल्लाह तआ़ला ने आप की उस ज़माने में भी ऐसी हिफ़ाज़त फ़रमाई ताकि कल कोई यह न कहने लगे कि अच्छा आज नबी बन कर आ गए हो, कल तो पार्टी में हमारे साथ थे, किसी को कहने की मजाल नहीं।

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल माऊन नं॰ 107)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

और असहाय को खाना देने पर ताकीद नहीं करता (प्रोत्साहन नहीं देता)।

अर्थात् ग़रीब लाचार की चिंता न स्वयं को है, न दूसरों को उनकी सहायता पर उभारता है। यह मानी हुई बात है कि यतीमों, असहायों की देखभाल करना उन पर कृपा करना दुनिया के प्रत्येक धर्म और मिल्लत में इसकी शिक्षा दी जाती है यह उन उत्तम चरित्रों में से हैं जिनकी अच्छाई पर तमाम बुद्धिमान् सहमत हैं। अब जो व्यक्ति इस प्राथमिक चरित्र से भी ख़ाली हो, समझ लो वह आदमी नहीं जानवर है। भला ऐसे को दीन से क्या संबंध और अल्लाह से क्या लगाव होगा?

सो ऐसे नमाज़ियों के लिए ख़राबी है जो अपनी नमाज़ से बेख़बर हैं।

अर्थात् नहीं जानते कि नमाज़ किसकी उपासना है और उसका क्या उद्देश्य है और कितनी सावधानी चाहती है। यह क्या नमाज़ हुई कि कभी पढ़ ली और कभी न पढ़ी। समय कुसमय खड़े हो गये, बातों में या दुनिया के धंधों में जान-बूझकर समय तं कर दिया, फिर पढ़ी भी तो चार टक्करें लगा लीं। कुछ ख़बर नहीं कि किसके सामने खड़े हैं और हाकिमों के हाकिम (अल्लाह) के सामने किस शासन से उपस्थित हो रहे हैं। क्या अल्लाह केवल हमारे उठने बैठने झुकने और सीधा होने को देखता है, हमारे दिलों पर नज़र रखता कि उनमें कहां तक विनम्रता और हार्दिक शुद्धता है। याद रखो यह तमाम हालात इस आयत में सम्मिलित हैं।

जो दिखावा करते हैं।

अर्थात् एक नमाज़ ही क्या, उनके दूसरे काम भी दिखावे से ख़ाली नहीं। तात्पर्य यह है कि उनका उद्देश्य अल्लाह से नज़र फेरकर केवल जगत को प्रसन्न करना है।

रुकू नं॰ 1

और बरतने की वस्तुएं मांगी नहीं देते।

अर्थात् ज़कात व सदक़ात आदि तो क्या अदा करते साधारण उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे डोल, रस्सी हंडिया, देग़ची, कुल्हाड़ी, सुई धागा आदि किसी को मांगी नहीं देते जिनके देने का दुनिया में सामान्य रिवाज़ है। कंजूसी का जब यह हाल हो तो दिखावे की नमाज़ से क्या लाभ होगा। अगर एक व्यक्ति अपने को नमाज़ी मुसलमान कहता और कहलाता है,म गर अल्लाह के साथ और जगत के साथ सहयोग नहीं रखता, उसका इस्लाम शब्द निरर्थक है और उसकी नमाज़ वास्तविकता से बहुत दूर है। यह दिखावा और दुराचार तो उन अभागों का काम होना चाहिए जो अल्लाह के दीन और आख़िरत पर कोई विश्वास नहीं रखते।

(सूरा अल कौसर नं॰ 108)

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें तीन आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

नि:संदेह हमने आपको कौसर दिया है।

कौसर का अर्थ बहुत भलाई का है अर्थात् बहुत अधिक भलाई और अच्छाई यहां किस वस्तु से तात्पर्य है इसके संबंध में बहुत से विचार हैं परंतु उन सब में अच्छा यही है कि इस शब्द के आधीन हर प्रकार की दुनिया और दीन की दौलतें और प्रत्यक्ष व परोक्ष नेमतें आती हैं, जो आपको या आपके कारण इस उम्मत को मिलने वाली थी। इन नामतों में से एक बड़ी नामत वह हौजे कौसर भी है जो इसी नाम से मुसलमानों में प्रसिद्ध है और जिसके पानी से हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ से महशर में अपनी उम्मत की प्यास बुझायेंगे।

चेतावनी :- चूंकि इस हौज़ का प्रमाण संक्षिप्त रूप से इस सूरा में और विस्तार रूप से बहुत सी हदीसों में आया है इसलिए इस पर विश्वास रखना प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है। हदीसों में उसका महशर में होना और कुछ से जन्नत में होना सिद्ध होता है। अधिकतर विद्वानों ने दोनों को इकट्ठा कर दिया है कि ''वास्तविक नहर जन्नत में है लेकिन उसका पानी हश्रत के मैदान में लाकर किसी हौज में इकट्ठा का दिया जायेगा'' दोनों का एक ही नाम होगा।

चौधरी चरण सिंह और उनके सिद्धांत

राकेश कपूर

इसमें कोई दोराय नहीं कि चौधरी चरण सिंह स्वतंत्र भारत के अभी तक के सबसे बड़े ऐसे किसान नेता हुए हैं जिन्होंने भारत की समूची अर्थव्यवस्था में ग्रामीण व कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को देश की प्राणवायु के रूप में निरूपित किया और सिद्ध किया कि भारत का पुनरुत्थान केवल गांवों के विकास से ही संभव है। चौधरी साहब के जन्मदिवस 23 दिसंबर को पूरे देश में उनकी याद में 'किसान दिवस' के रूप में मनाया जाता है परंतु राजनीति में उनके द्वारा स्थापित शुचिता व सादगी और ईमानदारी के सिद्धांत को ताक पर रख दिया जाता है। चौधरी साहब जब 1979 में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार को गिरा कर स्व. इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा दिये गये बाहर से समर्थन के बूते पर देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनका उद्देश्य सिर्फ़ कुर्सी हथियाना नहीं था बल्कि भारत की सामाजिक व आर्थिक वरीयताओं को पुनर्निधारित करना था। हालांकि उनकी सरकार ने कभी भी संसद का सामना नहीं किया क्योंकि इंदिरा ने अपनी पार्टी कांग्रेस का समर्थन उनसे बहुत जल्दी ही वापस ले लिया था जिसकी वजह से चौधरी साहब ने तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए लोकसभा भंग करने की अनुशंसा कर दी थी जिसकी वजह से 1980 में राष्ट्रीय चुनाव हुए थे जिनमें इंदिरा गांधी पुन: भारी बहुमत से सत्तारुढ़ हुई थीं।

चुनावों तक चौधरी साहब ही देश के प्रधानमंत्री बने रहे थे। अपनी पार्टी लोकदल को जनता पार्टी से अलग करते हुए चौधरी साहब ने स्वतंत्र चुनाव लड़ा था और इन चुनावों में कांग्रेस के बाद उनकी पार्टी के ही सर्वाधिक सांसद चुने गए थे हालांकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। मगर चोधरी साहब ने चुनावी पराजय के बाद अपना ज़्यादातर समय भारत की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में दिया। मगर 1984 में श्रीमति इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद चौधरी साहब ने अपनी पार्टी लोकदल का पुनर्गठन किया और इनमें अधिकाधिक दलित मूल के समाजवादी सोच के नेताओं को स्थान देते हुए इसका नाम दलित मज़दूर किसान पार्टी (दमकिपा) रखा। इस पार्टी में जार्ज फर्नांडीज से लेकर मुलायम सिंह यादव, राम विलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर और शरद पवार सरीखे नेता थे। मगर ये चुनाव श्रीमति गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि में हो रहे थे अत: स्व. राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को ऐतिहासिक सफलता मिली तथा समूचे विपक्ष का सफाया हो गया और भाजपा के नेता स्व. अटल बिहारी वाजपेयी तक ग्वालियर से चुनाव हार गये। मगर चौधरी साहब अपनी बाग़पत लोकसभा सीट जीते और ऐसा क्षेत्र से भी उनकी प्रत्याशी विजयी रहा। इस प्रकार उन्हें केवल दो सीटें मिलीं जबकि भाजपा को भी इतनी ही सीटें थीं।

1984 के चुनावों के दौरान मैं स्वयं चौधरी साहब के साथ चुनावी दौरा कर रहा था। इसी चुनावी दौरे के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक कॉलेज में आयोजित चुनावी जनसभा में ऐसा भाषण दिया जो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में अजर-अमर हो गया। यह ऐसा भाषण था जिसकी ऊंचाई स्वतंत्र भारत में आज तक किसी भी नेता ने छूने की हिम्मत नहीं दिखाई है। कांग्रेस ये चुनाव स्व॰ राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ रही थी और वह प्रधानमंत्री पद पर बैठ चुके थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जब की तो दोपहर का समय हो चुका था और जनसभा के लिए बने मंच के ठीक सामने सूरज आ रहा था। उन्होंने भाषण देना इस प्रकार शुरू किया ''मैनपूरी वालों तुमने दिखा दिया कि यहां जो भी बात करे वो सूरज का सामना करते हुए करे।' इसके बाद चौधरी साहब ने सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी की आलोचना शुरू की और समग्र विकास में खेती से लेकर कुटीर उद्योगों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस क्रम में वह परिवारवाद की राजनीति पर आये। 'भाइयो आपका एक बेटा है अजित सिंह। लोग मुझसे कहते हैं कि उसे सियासत में लाओ। मैं उन्हें जवाब देता हूं कि वो राजनीति में आने के लायक़ नहीं है क्योंकि वो एक किसान का बेटा नहीं बल्कि मिनिस्टर का बेटा है। वह कम्प्यूटर साइंस का बहुत बड़ा इंजीनियर है। उसे क्या पता गांवों में रेहट से कैसे सिंचाई की जाती है। उसे मालूम नहीं कि गांव में मढैया कैसे पड़ती है। किसानों और गांवों की मुश्किलात के बारे में उसे क्या पता हो सकता है इसलिए उसके राजनीति में आने का क्या मतलब।'

चौधरी साहब यह बात एक जनसभा में कह रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि राजनीति में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। उनके कहने का साफ मतलब था कि राजनीति कोई ख़ानदानी कारोबार नहीं है कि पिता की गद्दी बेटा संभाले। यह चौधरी साहब ही थे जो सार्वजनिक सभा में अपने एकमात्र पुत्र स्व. अजित सिंह को राजनीति में अयोग्य क़रार दे सकते थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि जिसे आज के राजनीतिज्ञों में महसूस तक करने की क्षमता नहीं है परंतु मुद्दा यह है कि जब चौधरी साहब 1987 में रोग शेया पर अचेत लेटे हुए तो उन्हीं के दल के स्व. देवीलाल और मुलायम सिंह उनसे अपने पुत्र अजित सिंह के राजनीति में आने के स्वीकृति पत्र पर अंगूठा लगवा कर ले जाये। यह लोकतंत्र के इतिहास की ऐसी बड़ी त्रासदी थी जिसने चौधरी साहब की राजनीति विरासत को पूरी तरह निगल लिया। विरोधाभास यह था कि चौधरी साहब को अपने प्रांत उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के नेता मुलायम सिंह पर बहुत भरोसा था और वह राज्य में उन्हें अपना उत्तराधिकारी जैसा ही मानते थे।

वही वजह थी कि 1974 में जब उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी भारतीय क्रांतिदल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी व बीजू पटनायक की कांग्रेस के अलावा स्वतंत्र पार्टी का विलय करके लोकदल बनाया था तो इस पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा का अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव को ही बनाया था। मगर

बाक़ी पेज 11 पर

न्यायाधीशों की नियुक्ति में कई संस्थाओं की भूमिका : सीजेआई

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन.वी. रमण ने कहा कि यह धारणा एक मिथक है कि ''न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं'', क्योंकि न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज़ एक हितधारक है। न्यायमूर्ति रमण ने यह बात विजयवाडा स्थित सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय में पांचवें श्री लवु वेंकेटेवरलु धर्मार्थ व्याख्यान में ''भारतीय न्यायपालिका - भविष्य की चुनौतियां'' विषय पर बोलते हुए कही।

सीजेआई ने कहा कि हाल के दिनों में न्यायिक अधिकारियों पर शारीरिक हमले बढ़े हैं और कई बार अनुकूल फैसला नहीं आने पर कुछ पक्षकार प्रिंट और सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के ख़िलाफ़ अभियान चलाते हैं और ये हमले ''प्रायोजित और समकालिक'' प्रतीत होते है। उन्होंने कहा कि लोक अभियोजकों के संस्थान को स्वतंत्र करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण आज़ादी दी जानी चाहिए और उन्हें केवल अदालतों के प्रति जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। न्यायमूर्ति ने कहा, ''इन दिनों न्यायाधीश खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं'' जैसे जुमलों को दोहराना चलन हो गया है। मेरा मानना है कि यह बड़े पैमाने पर फैलाए जाने वाले मिथकों में से एक है। तथ्य यह है कि न्यायपालिका इस प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज़ एक हितधारक है।''

उल्लेखनीय है कि हाल में केरल से सांसद जॉन ब्रिट्टस ने उच्च और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान संसद में कथित तौर कहा था कि न्यायाधीशों के ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की बात दुनिया में कहीं सुनाई नहीं देती। न्यायमूर्ति ने कहा रमण ने कहा कि कई प्राधिकारी इस प्रक्रिया में शामिल हैं, जिनमें केन्द्रीय क़ानून मंत्रालय, राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का कॉलेजियम, खुफिया ब्यूरो और अंतत: शीर्ष में कार्यकारी शामिल है, जिनकी ज़िम्मेदारी उम्मीदवार की योग्यता को परखने की है। मैं यह देखकर दुखी हूं कि जानकार व्यक्ति ही यह धारणा फैला रहे हैं। आखिरकार यह कथानक एक वर्ग को अनुकूल लगता हे। उन्होंने अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की कोशिश को लेकर केन्द्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा की गई कुछ नामों की अनुशंसा को अब भी केन्द्रीय कानून मंत्रालय की ओर से उच्चतम न्यायालय को भेजा जाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार मलिक मज़हर मामले में तयसीमा सीमा का अनुपालन करेगी। सीजेआई ने कहा कि क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों, खासतौर पर विशेष एजेंसियों को न्यायपालिका पर हो रहे दुर्भावनापूर्ण हमलों से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता और आदेश पारित नहीं करता, तब तक आमतौर पर अधिकारी जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं करते।

पांच वर्ष बाद सपा में 'चाचा' शिवपाल और 'भतीजा' अखिलेश एक साथ

राजनीतिक परिवारों में कलह कोई नई बात नहीं हैं बिहार में लालू यादव का परिवार दो खेमों में बंटा दिखाई दे रहा है तो हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (इनेलो) के बेटों अजय सिंह चौटाला तथा अभय सिंह चौटाला की राहें जुदा हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी (सपा) में 2017 में असहमति के स्वर उभरे तथा मुलायम के छोटे भाई शिवपाल यादव (अखिलेश के चाचा) ने सपा से संबंध तोड़कर 2019 में 'प्रगति समाजवादी पार्टी-लोहिया' (प्रसपा) का गठन करके उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में सपा के मुकाबले पर उतरने की घोषणा कर दी थी। इसी प्रकार पंजाब में शिअद भी फूट का शिकार हुई और प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।

इन दिनों जबकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में कुछ ही समय शेष है, सभी दल नए-नए चुनावी साथियों की तलाश और गठबंधन करने में जुटे हुए हैं। इसी श्रृंखला में जहां अखिलेश आधा दर्जन छोटे एवं क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर चुके हैं, वहीं उन्होंने चाचा शिवपाल यादव को मनाने की कोशिश भी शुरू कर रखी थी जिसका संकेत उन्होंने बीते वर्ष के 03 नवंबर को दे दिए थे। इसी श्रृंखला में 16 दिसंबर को अखिलेश ने शिवपाल यादव के निवास पर उनसे 40 मिनट तक बातचीत के बाद दोनों दलों में गठबंधन पर सहमति बन जाने की सूचना देते हुए टवीट में लिखा है 'प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात में गठबंधन की बात तय हुई।'' बातचीत के बाद जब दोनों नेता घर से बाहर आए तो वहां प्रतीक्षा कर रहे दोनों ही दलों के समर्थकों ने 'चाचा भतीजा ज़िन्दाबाद' के नारे लगाए।

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार इस सहमति के परिणामस्वरूप शिवपाल यादव के 15 से 20 के बीच विशेष लोग चुनाव में उतारे जा सकते हैं। इस अवसर पर सपा के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा ''अखिलेश यादव छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं।

सपा अगली सरकार बनाएंगी।' राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार आगामी चुनावों के दृष्टिगत यह भेंट बेहद महत्वपूर्ण है। चाचा भतीजे में सहमति से सपा को इन चुनावों में लाभ पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है।

पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच से अपने अभियान का आगाज़ करेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम अगले वर्ष न्यूजीलैंड में होने वाले वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच से अपने अभियान का आगाज़ करेगी। दोनों टीमों के बीच यह मैच छह मार्च को खेला जाएगा जबकि टूर्नामेंट का उद्घाटन मुक़ाबला चार मार्च को न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व कप का ताजा कार्यक्रम जारी किया है। 31 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 31 मैच खेले जाएंगे जिसमें आठ टीमें शिरकत कर रही हैं।

पहला सेमीफाइनल वेलिंगटन में 30 मार्च को खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 31 मार्च को जबकि ख़िताबी मुक़ाबला तीन अप्रैल को होगा। दूसरी सेमीफाइनल और फाइनल क्राइस्ट चर्च में होगा।

भारत का विश्व कप का कार्यक्रम

बनाम	तारीख़
पाकिस्तान	06 मार्च
न्यूज़ीलैंड	10 मार्च
वेस्टइंडीज	12 मार्च
इंग्लैंड	16 मार्च
आस्ट्रेलिया	19 मार्च
बांग्लादेश	22 मार्च
दक्षिण अफ्रीका	27 मार्च

पाक ने वेस्टइंडीज से जीती टी-20 सीरीज

पाकिस्तान ने नेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को नौ रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाकर सीरीज पर कब्ज़ा कर लिया है। पाकिस्तान ने टीस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 172 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज की टीम 20 ओवर में 163 रन ही बना पाई थी। पाकिस्तान की पारी में मुहम्मद रिज़वान ने सर्वाधिक 38 रन बनाए, जबकि शादाब खान 12 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद रहे। विंडीज की ओर से ब्रेंडन किंग ने 67 रनों की पारी खेली। शाहीन आफरीदी ने तीन विकेट लिए।

मुक्केबाज़ी सहित तीन खेलों पर ओलंपिक 2028 से बाहर होने का ख़तरा

मुक्केबाज़ी, भारोत्तोलन और मॉडर्न पेंटाथलान को लास एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलम्पिक खेलों में अपना स्थान बरकरार रखने के लिए 18 माह के अंदर अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सतिमि (आईओसी) के अध्यक्ष थॉमस बाक ने मुक्केबाज़ी और भारोत्तोलन के शासी निकायों के बारे में कहा कि वे हमेशा समस्याएं पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इन खेलों में नेतृत्व से जुड़े मसलों और भ्रष्टाचार और डोपिंग के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। मॉडर्न पेंटाथलान को आइओसी ने अपनी स्पर्धाओं से घुड़सवारी को हटाने के लिए कहा है जिस पर खिलाड़ियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

इन तीनों खेल को ओलंपिक 2028 के कार्यक्रम की शुरूआती सूचि में शामिल नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम को मंज़ूरी के लिए फरवरी में आईओसी सदस्यों के सामने रखा जाएगा। सूचि में स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिग शामिल हैं। ये तीनों खेल पहली बार तोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए थे। इससे वे भविष्य में ओलंपिक प्रसारण कार्यक्रम से होने वाली आय हासिल करने के हक़दार भी बन जाएंगे जो प्रति खेल कम से कम एक करोड़ 50 लाख डॉलर है। जिन तीन खेलों को हटाया गया है उनके पास अब भी सूचि में शामिल होने का मौक़ा रहेगा। बाक ने कहा कि उन्हें आईसीसी कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को अपने खेल के शासन और संगठनात्मक संस्कृति में बदलावों से संतुष्ट करना होगा।

जोकोविक के आस्ट्रेलियन ओपन में खेलने पर संशय

विश्व के नंबर-वन टेनिस प्लेयरा सर्बिया के नोवाक जोकोविक के 17 जनवरी से शुरू होने जा रहे आस्ट्रेलियन ओपन में खेलने पर अभी भी संशय बना हुआ है। 20 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता खिलाड़ी ने अभी तक आस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों को पुष्टि नहीं की है कि उन्होंने कोविड-19 का टीका लगवाया है या नहीं, क्योंकि बिना टीकाकरण वाले खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकेंगे। आस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के निदेशक क्रैग टिली ने उन ख़बरों को ख़ारिज कर दिया है, जिनमें नौ बार के आस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियन जोकोविक को चिकित्सकीय छूट दिए जाने की बात कही गई थी। टिली ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि क्या जोकोविक आस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में खेलेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी का नाम 104 पुरुष खिलाड़ियों की सूचि में है, लेकिन अभी भी उनके खेलने पर संदेह बना हुआ हे।

एडिलेड से 2022 सत्र की शुरुआत करेंगी बार्टी

महिलाओं में विश्व की नवंबर-1 टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी 2022 में अपने सत्र की शुरुआत जनवरी के पहले सप्ताह में होनी है, वह आस्ट्रेलियन ओपन के अभ्यास टूर्नामेंट एडिलेड इंटरनेशनल में हिस्सा लेकर करेंगी। विंबलडन चैम्पियन ने आखिरी बार सितंबर के शुरुआत में यूएस ओपन में हिस्सा लिया था। आस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियन नाओमी ओसाका और यूएस ओपन की विजेता एम्मा राडूकानू मेलबर्न पार्क में होने वाले दो महिला वार्म अप टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी।

शरीर में हार्मोन्स के स्राव में गड़बड़ी व मानसिक समस्या के फलस्वरूप व्यक्ति अधिक आहार या कम आहार करने लगता है

कोरोना के कारण लोगों को अधिक सतर्कता बरतने की नसीहतें दी जाती रही हैं, बल्कि यों कहें कि आम व्यक्ति पहले से अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति लगाव रख रहा है, चाहे वह खाने पीने में हो, रहन सहन में या स्वास्थ्य संबंधी अन्य ज़रूरतें। व्यक्ति की उम्र, लिंग व लंबाई के अनुसार एक निश्चित अनुपात में आहार की आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक आहार व कम दोनों ही स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। शरीर में हार्मोन्स के स्राव में गड़बड़ी व मानसिक समस्या के फलस्वरूप व्यक्ति अधिक आहार या कम आहार करने लगता है। यह बीमारी नहीं है, एक बड़ी समस्या है। लम्बे समय तक अधिक आहार व कम आहार का सेवन करने का अर्थ घातक बीमारियों को सीधा आमंत्रण देना है। अधिक आहार तथा व्यक्ति को भूख न लगने पर भी हर वक्त आहार ग्रहण करने की आदत होना ठीक नहीं।

कारण

एंड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव में गड़बडी।

मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण मस्तिष्क में उपस्थित हाईपोथेलेमस का खराब होना जिसके कारण पेट भरने पर भी संतुष्ट नहीं होती है।

मानसिक रोग : ड्रिपेशन, तनाव, हीनता की भावना, असुरक्षा की भावना, खालीपन, एकाकीपन आदि।

अधिक देर तक टीवी देखना।

त्याग करें इनका

कार्बोज : अधिक कार्बोजयुक्त खाद्य पदार्थ जैसे आलू, शकर केक, साबूदाना, चावल आदि।

वसा : घी, तेल, मिठाईयों का कम उपयोग। फास्ट फूड व जंग फूड : कुरकुरे, बर्गर, हॉट-डाग।

मीठे फल जैसे आम, पपीता, केला, चीकू, व अंगूर आदि।

बाजार में उपलब्ध डिब्बाबंद फूड कोल्ड ड्रिंक व प्रिजर्व फूड।

प्रोटीन : मलाईरहित दूध, छिल्के वाली दालें, भुने चने व अंकुरित अनाज का अधिक सेवन।

तरल पदार्थ : खाना खाने के पहले 1 गिलास पानी लें।

मिनरल और विटामिन : खट्टे फलों का अत्यधिक उपयोग, जैसे सेब फल, संतरा, कच्चा जाम, अनार, नाशपाती।

रेशेदार पदार्थ : सलाद, छिल्के वाली दाल, आटा चौकर सहित आदि का अत्यधिक सेवन करें।

उपरोक्त आहार के लेने से अधिक खाने की समस्या होने पर भी शरीर में कम कैलौरी पहुंचेगी जिससे मोटापे की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। शारीरिक क्रियाओं को बढ़ाने से भी अधिक खाना खाने की समस्या में सुधार होता है।

कम खाना : भूख न लगना या बहुत कम मात्रा में आहार का सेवन करना।

लम्बे अंतराल तक उपवास करना।

बुखार, पेट संबंध बीमारियां।

शरीर में आहार का अपाचन।

वजन कम करना, तनाव, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना, कार्य की अधिकता होना।

आहार का प्रयोग

अधिक कार्बोजयुक्त खाद्य पदार्थ का सेवन।

क्रीम, बटर, घी, तले हुए पदार्थ खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन।

नारियल पानी, जूस, नींबू पानी का अधिक सेवन।

खाना खाने से पहले व बीच में पानी न लें।

भूख लगाने की दवाओं का उपयोग करें।

उपरोक्त आहार का सेवन करने से कम आहार लेने पर भी शरीर को अधिक कैलोरी एवं वसा मिलेगी जिसके कारण कमजोरी, काम में मन न लगना, जल्दी थक जाना, वजन में कमी, चिड़चिड़ापन आदि से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। चाय व काफी कम पिएं, क्योंकि यह भूख कम करती हैं। कब्ज़ से बचें, पेट साफ रखें। ❑❑

शेष.... ककाबुल तक पहुंचने की...

रही मानवीय सहायता का स्वागत किया है। यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भारत की ओर से अफग़ानिस्तान में दो दशकों के दौरान खड़ी की गई तीन अरब डॉलर की परियोजनाओं का भी ज़िक्र किया, जिनमें अफग़ान नेशनल एसेंबली कॉम्पलेक्स, हेरात में सलमा बांध और अनेक बिजली संयंत्र और आईटी प्रशिक्षण केन्द्र शामिल है। स्टेनकजई ने कहा कि उनकी सरकार विकास परियोजनाओं के रूप में भारत की व्यापक मौजूदगी का स्वागत करेगी। हालांकि यह सब अभी अनिश्चित है, क्योंकि वैश्विक समुदाय से तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने का इंतज़ार किया जा रहा है। इसमें ज़रा भी संदेह नहीं कि अफग़ानों के बीच भारत और भारतीय काफी लोकप्रिय हैं, जो कि ऐतिहासिक रूप से इलाज, उच्च शिक्षा, नौकरियों और कारोबार के सिलसिले में भारत आते रहे हैं। पिछले बीस सालों के दौरान उनमें से अनेक अपने परिवारों के साथ भारत में काम कर रहे हैं और यहीं बस गए। अफग़ानों के लिए भारत 'काबुलीवाला' के समय से दूसरा घर रहा हे। हालांकि राजनीतिक अनिश्चितताओं ने लोगों के इस मेलजोल को समय-समय पर बाधित किया है।

तालिबान की अपनी आंतरिक मुश्किलें कम नहीं हैं, जिनकी वजह से पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण के बावजूद वहां राजनीतिक अस्थिरता है। वे इस्लामिक स्टेट (आईएस) से लड़ रहे हैं, जो कि गंभीर ख़तरा बनकर उभरे हैं और इस्लाम का ऐसा संस्करण लाना चाहते हैं जो कि तालिबान से अभी अधिक कट्टर है। अफग़ान अर्थव्यवस्था में काम करने वाले या तो देश छोड़कर भाग गए हैं या अशरफ़ ग़नी की पिछली सरकार का हिस्सा होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। महिलाओं को काम से बाहर रखा जाता है उन्हें घरों तक ही सीमित रखा जाता है, भले ही वे अकेले कमाने वाली क्यों न हों। यह एक गंभीर दोहरी सामाजिक और आर्थिक समस्या पैदा कर रहा है। तालिबान को संचालित करने वाला पाकिस्तान ही है, जो चाहता है कि दुनिया मानवीय कारणों से संकट में अफग़ानों की मदद करे। लेकिन वह यह भी चाहता है कि अफग़ान अपने स्वयं के पश्तूनों और अल्पसंख्यकों को भी सकारात्मक बदलाव से दूर रखे। दोनों पक्षों के गहरे रुढ़िवादी तत्व खुद को पोषित करने की कोशिश कर रहे हैं और बदलाव की हवाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।❑❑

शेष.... यह ज़रूरी नहीं कि....

(वोट) दे देते हैं।

प्रश्नः- भाजपा के ख़िलाफ़ ताक़तवर चुनौती पेश करने के लिए विपक्ष को क्या करना चाहिए..?

उत्तरः- चार पहलुओं को ठीक करना होगा, कोई समन्वयकारी चेहरा होना चाहिए, कोई नैरेटिव हो, कोई युक्ति होनी चाहिए, जैसा कि एकजुट विपक्ष या कोई भी राजनैतिक दल होता है, और उसके साथ-साथ मशीनरी होनी चाहिए, इसमें आपको एक चीज़ और जोड़नी होगी, वह यह कि भाजपा का मुक़ाबला करने के लिए उसे खासा चपल और चुस्त दुरुस्त होना होगा, चाहे वह ज़मीनी स्तर पर संदेश फैलाना हो या सियासी दांव पेंच हों, अगर आपने ये पहलू दुरुस्त कर लिए तो आप भाजपा के ख़िलाफ़ चुनौती पेश कर सकते हैं।

प्रश्नः- भाजपा की क्या कमज़ोरियां हैं..?

उत्तरः- जहां कहीं भी उन्हें कठिन सियासी चुनौती का सामना करना पड़ा, वे विरोधियों को अनिवार्य रूप से रोक पाने में नाकाम रहे हैं, कांग्रेस को भले उन्होंने आसानी से शिकस्त दी है। कांग्रेस के ख़िलाफ़ उनकी सफलता का दर 95 प्रतिशत है लेकिन दूसरों के ख़िलाफ़ यह बहुत अच्छा नहीं रहा है। पूर्वी और दक्षिणी राज्यों को ही देख लें -बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू और केरल जहां लोकसभा की करीब 200 सीटें हैं, उन सभी जगहों पर भाजपा केवल 54 सीटों तक सीमटी हुई है। इसके पास बिहार में 17 सीटें, प0 बंगाल में 18, ओडिशा में 12, तेलंगाना में चार, तमिलनाडु और आंध्र में एक भी सीट नहीं है। यह बताता है कि इन क्षेत्रों में मज़बूत और एकजुट विपक्ष नहीं होने के बावजूद करीब 40 प्रतिशत लोकसभा सीटों में वह सफलता हासिल नहीं कर पाई। पिछले 10 सालों में वहां व्यक्तिगत पार्टियां और उनके नेता भाजपा के राजनैतिक हमलों का सामना करने में सक्षम रहे हैं। पश्चिम और उत्तर भारत में भाजपा एक ताक़त है - अगर आप कर्नाटक से कश्मीर तक एक सीध ी रेखा खींचते हैं और गुजरात समेत पश्चिम की ओर देखते हैं, तो यह वह क्षेत्र है जहां भाजपा सचमुच सब कुछ जीत रही है, लेकिन इस इलाक़े में किसी भी वजह से अगर वे 100 सीटें हार गए तो यह उन्हें काफी कमज़ोर कर देगा, विशेषकर पूर्व और दक्षिण में उनकी मौजूदा अनुपस्थिति को देखते हुए।

प्रश्नः- क्या 2024 तक ऐसा करने के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त समय है?

उत्तरः- दो साल वक्त कम नहीं होता, इसलिए मैं सब कुछ 2024 पर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन, अगर आपको वाकई भाजपा का मुक़ाबला करना है, तो आपके पास 7-10 साल का एक दीर्घकालिक नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें 2024 में एक साथ आगर भले हरा देंगे लेकिन उस ज़मीन पर बने रहने के लिए आपको उन चार चीज़ों को लगातार मज़बूत करना होगा जिन्हें मैंने रेखांकित किया है।❑❑

यूपी में अकबर इलाहाबादी का नाम बदलने पर विवाद

उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कवि अकबर इलाहाबादी का नाम बदलने पर विवाद खड़ा हो गया है। योगी सरकार के इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के तीन साल बाद मंगलवार को यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी का नाम अकबर प्रयागराजी कर दिया गया। इस पर विवाद खड़ा होने पर आयोग ने हैकिंग का दावा करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मुद्दे पर हंगामा होने के बाद यूपीएचईसीएस के उप सचिव शिव जी मालवीय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वेबसाइट हैक की गई है और महान कवि अकबर श्इलाहाबादीश का नाम बदलकर अकबर श्प्रयागराजीश करना भ्रामक है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर ऐसा कोई नाम दर्ज नहीं किया है। इसे ठीक किया जा रहा है। यूपीएचईएससी की विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि साइबर सेल से जांच की मांग की जा रही है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आयोग की हिंदी वेबसाइट को बहाल कर दिया गया है और अंग्रेजी पोर्टल को बहाल करने का काम जारी है।घटना की शिकायत पुलिस साइबर सेल में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए की गई है। यूपीएचईएससी, राज्य सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो राज्य के 331 सरकारी सहायता प्राप्त कालोजों में प्रिंसिपल और सहायक शिक्षकों की नियुक्ति करती है।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

हैं। सत्तारुढ़ पक्ष और विपक्ष दोनों को ऐसे अवसरों की संभावनाएं बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। यह याद रखना ज़रूरी है कि बहस संसद की प्राणवायु है।

एक बड़ा सत्य यह भी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर हमारी संसद है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भारतीय लोकतंत्र की आन-बान-शान हैं। लोकसभा में लंबी चौड़ी बहस के बाद कितने ही विधेयक राज्यसभा में पहुंचते हैं। वहां फिर बहस होती है, अगर ऐसा है तो यह परंपरा है। तर्क वितर्क को चलना लोकतंत्र में सहमति के मामले में बहुत आवश्यक भी है। कभी लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा का स्तर बहुत गरिमापूर्ण हुआ करता था, जिन लोगों ने राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, आचार्य जे.वी. कृपलानी, उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रीमति सुषमा स्वराज और अन्य नेताओं की बहस सुनी है तो उन्हें इस बात का अहसास हो रहा होगा कि आज बहस का स्तर कितना गिर गया है कि संसद के दोनों सदनों में जाना ही पसंद नहीं करते सांसद। या फिर हाज़िरी लगाई या एक दो घंटे मुंह दिखाई की और लौट गए। बीते संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर बच्चों को कोई बात बार-बार कही जाए तो वे भी ऐसा नहीं करते। कृपया परिवर्तन लाइये, वर्ना परिवर्तन खुद-ब-खुद हो जाएगा। प्रधानमंत्री की फटकार एक तरह से साफ चेतावनी है कि सांसद संसद की गरिमा को समझें और जनप्रतिनिधि के तौर पर आचरण करें वर्ना जनता ही उन्हें खुद बदल देगी। संसदीय मामलों के जानकार याद करते हैं कि कभी संसद में विद्वानों की भरमार थी। 70 प्रतिशत से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो न केवल कानून के जानकार थे बल्कि क़ानून की विभूतियों में हम उनका नाम रख सकते थे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के शिक्षाविद् होते थे। संसद में जो बहस होती थी, आज के सांसद अगर उनका अध्ययन करें तो शायद कुछ अपवादों को छोड़कर लोग उसका अर्थ ही नहीं समझ सके। भारत का लोकतंत्र वैचारिक धरातल पर लड़ा जाता रहा है, इसमें व्यक्तिगत दुश्मनी की कोई जगह नहीं होती थी। अब केवल लड़ाई आरोपों प्रत्यारोपों की रह गई है। अनुशासनहीनता संसद में सांसदों को अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देना चाहिए लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता में लगातार गिरावट आती जा रही है। विपक्ष का काम नीतियों पर प्रहार करना होता है और हंगामे को वह अपना अधिकार समझ बैठे हैं। हमारा मानना है कि हंगामा स्वस्थ रूप से किसी चीज़ के विरोध के रूप में होना चाहिए लेकिन आजकल हंगामा महज़ हंगामे के लिए ही किया जाने का प्रचलन चल पड़ा है। जिस सदन में बैठकर राष्ट्र निर्माण की बातें की जाती हों उस सदन में बैठकर हंगामा करना और तोड़ फोड़ करना सांसदों का आचरण के बिल्कुल विपरीत है। हमने जब संसदीय प्रणाली अपनाई तो यह तय था कि भारत आम जनता की इच्छा के अनुरूप ऐसा शासन चलाएगा जिसे कल्याणकारी कहा जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर एक-एक मिनट पर लाखों रूपया खर्च होता है। एक तो सांसद संसद में ग़ैर हारित रहते हैं, जो मौजूद होते हैं वह हंगामा करते हैं। विपक्षी सांसदों ने संसद की गरिमा को तार-बार करके रख दिया है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है। संसद की सर्वोच्चता बनाने के लिए पहले नियमों का पालन करना ज़रूरी है। नियमों का पालन होगा तो संसद की गरिमा बचेगी। अगर सांसद दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें अपने भीतर खुद झांकना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी पार्टी के सांसद को तो फटकार लगाई ही है लेकिन इसका संदेश दूसरी पार्टियों के लिए भी है। सभी राजनीतिक दलों को अपने सांसदों को संसद की गरिमा के अनुरूप आचरण करने, संसद में उपस्थिति देकर संसद की बहस में भाग लेने और मुद्दों को गंभीरता से समझने के लिए सीख देनी होगी। हम सब को यह विचार करने की आवश्यकता है कि संसद की गरिमा और सम्मान को कैसे बचाया जाए। सत्तारुढ़ दल को भी विपक्ष को अवसर देने की रणनीति बनाने के बारे में सोचना की आवश्यकता है, विपक्ष को चाहिए कि सत्तारुढ़ को सहयोग वाली मुद्रा अपनाए न कि रोड़ा अटकाने वाली।❑❑

शेष.... चौधरी चरण सिंह और उनके सिद्धांत

चौधरी साहब के देहांत के बाद जिस तरह राजनीति ने करवट ली उसमें स्व. देवीलाल और मुलायम सिंह की राजनीति में परिवारवाद के सबसे बड़े संस्थापक निकले।

इतना ही नहीं नेताओं ने चौधरी साहब द्वारा तैयार किया गया समूचा ग्रामीण वोट बैंक भी जातियों में विभाजित कर डाला जबकि चौधरी साहब जातिवाद के कट्टर विरोधी थे और पक्के आर्य समाजी थे। वह धर्मशालाओं तक के नाम जातिपरक रखने के कट्टर विरोधी थे और महिला शिक्षा व अंतरजातीय विवाह के प्रबल समर्थक थे।

मगर विडंबना देखिये कि परिवारवादी राजनीति के घरघोर विरोधी स्व. चौधरी चरण सिंह की विशाल राजनैतिक विरासत को पहले उनके पुत्र स्व. अजित सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केवल पांच जाट बहुल जिलों तक सीमित कर डाला और अब उनके पौत्र जयंत चौधरी इसे विस्तारित करने के प्रयास में हैं परंतु यह बहुत दुष्कर्य कार्य है क्योंकि चौधरी साहब जैसा सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञ होना अब सागर में मोती ढूंढने जैसा हो गया है।

आज के किसान नेता क्या उनकी इस क्या उनकी इस बात पर गौर फरमायेंगे कि विकास का मार्ग खेतों से ही होकर गुज़रता है। मगर क्या गज़ब हुआ कि हमने खेतों में काम करने वाले मेहनतकश हाथों को जातियों व सम्प्रदायों के खांचों में बांट दिया है। 1985 में लिखी अपनी पुस्तक 'नाइटमेयर ऑफ इंडियर इकोनॉमी' में चौधरी साहब ने साफ कर दिया था कि स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर ही भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी परंतु भारत के लोकतंत्र में आम आदमी के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपने का उनका सबसे बड़ा सिद्धांत राजनीति में परिवारवाद के निषेध का था। अतः जो भी राजनीतिज्ञ उनकी विरासत का दम भरते हैं उन्हें सबसे पहले इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **26 Dec.2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

शांति मिशन कैलेंडर 2022

1443-44 हिजरी

जनवरी जमादुल अव्वल-जमादुल आख़िर 1443 हि. January

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
30 (26)	31 (27)	13 लोहड़ी	14 मकर सक्राति	26 गणतंत्र दिवस		1 जमादुल अव्वल 27
2 (28)	3 (29)	4 (30)	5 जमादुल आख़िर 1	6 (2)	7 (3)	8 (4)
9 (5)	10 (6)	11 (7)	12 (8)	13 (9)	14 (10)	15 (11)
16 (12)	17 (13)	18 (14)	19 (15)	20 (16)	21 (17)	22 (18)
23 (19)	24 (20)	25 (21)	26 (22)	27 (23)	28 (24)	29 (25)

फरवरी जमादुल आख़िर-रजब 1443 हि. February

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
		1 जमादुल आख़िर 28	2 (29)	3 रजब 1	4 (2)	5 (3)
6 (4)	7 (5)	8 (6)	9 (7)	10 (8)	11 (9)	12 (10)
13 (11)	14 (12)	15 (13)	16 (14)	17 (15)	18 (16)	19 (17)
20 (18)	21 (19)	22 (20)	23 (21)	24 (22)	25 (23)	26 (24)
27 (25)	28 (26)					5 बसंत पंचमी

मार्च रजब-शाबान 1443 हि. March

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
17 होली	18 दुलहंडी	1 रजब 27	2 (28)	3 (29)	4 (30)	5 शाबान 1
6 (2)	7 (3)	8 (4)	9 (5)	10 (6)	11 (7)	12 (8)
13 (9)	14 (10)	15 (11)	16 (12)	17 (13)	18 (14)	19 (15)
20 (16)	21 (17)	22 (18)	23 (19)	24 (20)	25 (21)	26 (22)
27 (23)	28 (24)	29 (25)	30 (26)	31 (27)		18 शबे बरात

अप्रैल शाबान-रमज़ानुल मुबारक 1443 हि. April

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
10 राम नौमी	14 बैसाखी	14 महावीर जयंति	15 गुड फ्राइडे	29 जुम्मतुल विदा	1 शाबान 28	2 (29)
3 रमज़ान 1	4 (2)	5 (3)	6 (4)	7 (5)	8 (6)	9 (7)
10 (8)	11 (9)	12 (10)	13 (11)	14 (12)	15 (13)	16 (14)
17 (15)	18 (16)	19 (17)	20 (18)	21 (19)	22 (20)	23 (21)
24 (22)	25 (23)	26 (24)	27 (25)	28 (26)	29 (27)	30 (28)

मई रमज़ानुल मुबारक-शव्वाल 1443 हि. May

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
1 रमज़ान 29	2 (30)	3 शव्वाल 1	4 (2)	5 (3)	6 (4)	7 (5)
8 (6)	9 (7)	10 (8)	11 (9)	12 (10)	13 (11)	14 (12)
15 (13)	16 (14)	17 (15)	18 (16)	19 (17)	20 (18)	21 (19)
22 (20)	23 (21)	24 (22)	25 (23)	26 (24)	27 (25)	28 (26)
29 (27)	30 (28)	31 (29)	3 ईदुल फित्र	16 बुधपूर्णिमा		

जून ज़ीक़ादा 1443 हि. June

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
			1 ज़ीक़ादा 1	2 (2)	3 (3)	4 (4)
5 (5)	6 (6)	7 (7)	8 (8)	9 (9)	10 (10)	11 (11)
12 (12)	13 (13)	14 (14)	15 (15)	16 (16)	17 (17)	18 (18)
19 (19)	20 (20)	21 (21)	22 (22)	23 (23)	24 (24)	25 (25)
26 (26)	27 (27)	28 (28)	29 (29)	30 (30)		

जुलाई ज़िलहिज्जा 1443-मुहर्रम 1444 हि. July

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
31 मुहर्रम 1	10 ईदुल अज़्हा				1 ज़िल हिज्जा 1	2 (2)
3 (3)	4 (4)	5 (5)	6 (6)	7 (7)	8 (8)	9 (9)
10 (10)	11 (11)	12 (12)	13 (13)	14 (14)	15 (15)	16 (16)
17 (17)	18 (18)	19 (19)	20 (20)	21 (21)	22 (22)	23 (23)
24 (24)	25 (25)	26 (26)	27 (27)	28 (28)	29 (29)	30 (30)

अगस्त मुहर्रम - सफ़र 1444 August

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
11 रक्षाबंधन	1 मुहर्रम 2	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)
7 (8)	8 (9)	9 (10)	10 (11)	11 (12)	12 (13)	13 (14)
14 (15)	15 (16)	16 (17)	17 (18)	18 (19)	19 (20)	20 (21)
21 (22)	22 (23)	23 (24)	24 (25)	25 (26)	26 (27)	27 (28)
28 (29)	29 सफ़र 1	30 (2)	31 (3)	9 यौमे आशूरह	15 स्वतंत्रता दिवस	19 जन्माष्टमी

सितम्बर सफ़र-रबीउल अव्वल 1444 September

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
				1 सफ़र 4	2 (5)	3 (6)
4 (7)	5 (8)	6 (9)	7 (10)	8 (11)	9 (12)	10 (13)
11 (14)	12 (15)	13 (16)	14 (17)	15 (18)	16 (19)	17 (20)
18 (21)	19 (22)	20 (23)	21 (24)	22 (25)	23 (26)	24 (27)
25 (28)	26 (29)	27 (30)	28 रबीउल अव्वल 1	29 (2)	30 (3)	

अक्तूबर रबीउल अव्वल-रबीउल आख़िर 1444 October

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
30 (4)	31 (5)	2 गाँधी जयंति	5 दशहरा	24 दीवाली	27 भैयादूज	1 रबीउल अव्वल 4
2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)	7 (10)	8 (11)
9 (12)	10 (13)	11 (14)	12 (15)	13 (16)	14 (17)	15 (18)
16 (19)	17 (20)	18 (21)	19 (22)	20 (23)	21 (24)	22 (25)
23 (26)	24 (27)	25 (28)	26 (29)	27 रबीउल आख़िर 1	28 (2)	29 (3)

नवम्बर रबीउल आख़िर-जमादुल अव्वल 1444 November

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
8 गुरुनानक जयन्ति		1 रबीउल आख़िर 6	2 (7)	3 (8)	4 (9)	5 (10)
6 (11)	7 (12)	8 (13)	9 (14)	10 (15)	11 (16)	12 (17)
13 (18)	14 (19)	15 (20)	16 (21)	17 (22)	18 (23)	19 (24)
20 (25)	21 (26)	22 (27)	23 (28)	24 (29)	25 (30)	26 जमादुल अव्वल 1
27 (2)	28 (3)	29 (4)	30 (5)			

दिसम्बर जमादुल अव्वल-जमादुल आख़िर 1444 December

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधावार	THU जुमेरात	FRI जुमा	SAT शनिवार
25 क्रिस्मसडे				1 रबीउल आख़िर 6	2 (7)	3 (8)
4 (9)	5 जमादुल अव्वल 10	6 जमादुल अव्वल 11	7 (12)	8 (13)	9 (14)	10 (15)
11 (16)	12 (17)	13 (18)	14 (19)	15 (20)	16 (21)	17 (22)
18 (23)	19 (24)	20 (25)	21 (26)	22 (27)	23 (28)	24 (29)
25 (30)	26 जमादुल अव्वल 1	27 (2)	28 (3)	29 (4)	30 (5)	31 (6)

साप्ताहिक शांति मिशन, मदनी हाल, 1-बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादकः- मोहम्मद सालिम, फोनः- 23311455, 23317729, फैक्सः- 23316173